राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 88 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,01 अक्टूबर 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

मप्र में दूसरे डोज का आंकड़ा डेढ़ करोड़ पार

भोपाल, (एजेंसी)। मप्र में कोविड टीकाकरण महाअभियान में कोरोना वैक्सीन की डेढ़ करोड़ से अधिक दूसरी डोज नागरिकों को लगाई जा चुकी है। प्रदेश में वैक्सीन की 4 करोड़ 82 लाख 2 हजार 646 प्रथम डोज लगाई गई है। संचालक एनएचएम (टीकाकरण) डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 6 करोड़ 32 लाख 51 हजार 229 कोरोना के टीके लगाए जा चुके है। इनमें 4 करोड़ 82 लाख 2 हजार 646 प्रथम डोज और एक करोड़ 50 लाख 48 हजार 583 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

बंगाल के भवानीपुर में 53.32 फीसदी मतदान

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर गुरुवार को मतदान पूरा हो गया है है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल के बीच कड़ी टक्कर है। सीपीआई (एम) की ओर से श्रीजिब विश्वास मैदान में थे। हालात के मद्देनजर मतदान वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। तीन अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि भवानीपुर के अलावा जांगीपुर, समशेरगंज विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ। भवानीपुर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। यहां शाम पांच बजे तक 53.32 फीसदी मतदान हुआ।

वीआर चौधरी ने संभाली वायुसेना की कमान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को यहां भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 42 साल तक सेवा के पश्चात गुरुवार को सेवानिवृत्त होने पर वायुसेना की कमान एयर चीफ मार्शल चौधरी को सौंपी, जिन्होंने चीन के साथ संकट के दौरान लद्दाख सेक्टर की कमान संभाली थी। चौधरी दिसंबर 1982 में वायुसेना की युद्धक टीम में शामिल हुए थे।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने गुरुवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। पीपीएफ और एनएससी पर सालाना ब्याज दर क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें 2021-22 की तीसरी तिमाही (एक अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर 2021) के लिए यथावत रहेंगी।

देश में पेंशन, सिलेंडर से लेकर चेकबुक तक, आज से बदलेंगे ये नियम

नई दिल्ली ■ एजेंसी

एक अक्टूबर 2021 यानी शुक्रवार से भारत में रुपए- पैसे से जुड़े नौ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है । नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, कुछ बैंकों की चेकबुक, आदि शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर, मिलेगी राहत

चेकबुक बंद: तीन बैंकों के ग्राहकों पर असर

शुक्रवार से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन (एमआईसीआर) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएससी) अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है।

ऑटो डेबिट : ग्राहकों की मंजूरी जरूरी

1 अक्टूबर, 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम

तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में इस साल एलपीजी सिलेंडर एक जनवरी को 694 रुपया का था, लेकिन अब बढ़कर 884.50 रुपए का हो गया है। यानी इसमें 190.50 रुपए की तेजी आई है। मौजूदा समय में कोलकाता में इसका दाम 911 रुपए, मुंबई में 884.5 रुपए और चेन्नई में 900.5 रुपए है। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है।

पेंशन : जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र

एक अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।

बदल रहे हैं पोस्टल ऑफिस एटीएम के नियम

पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं, जो शुक्रवार से लागू होंगे। एक महीने में एटीएम पर कितने वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं, इसमें बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर, 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए होगा। इस पर जीएसटी भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए शुल्क वसूलेगा। एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपए चार्ज लिया जाएगा। वहीं एटीएम कार्ड खोने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने 300 रुपए के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसी तरह एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपए और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। यदि बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, डाक विभाग ने एटीएम पर किए जा सकने वाले मुफ्त वित्तीय लेनदेन की संख्या को भी सीमित कर दिया है। इंडिया पोस्ट पांच मुफ्त लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन 10 रुपए व जीएसटी वसूलेगा।

तीन कृषि कानूनों का विरोधः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सड़कों पर जमे बैठे किसानों को हटाने क्या कदम उठाए गए ?

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए क्या कर रही है? शीर्ष अदालत ने एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़कों को हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी समस्या का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और यह एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा कि हम पहले ही कानून बना चुके हैं और आपको इसे लागू करना होगा। अगर हम अतिक्रमण करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने आपके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। कुछ शिकायतें हैं जिनका निवारण किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) केएम नटराज से विशेष रूप से पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है?

आवेदन दायर करने केंद्र को मिली अनुमति

शीर्ष कोर्ट के जवाब में मेहता ने कहा कि बहुत ही उच्च स्तर पर एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हमने उन्हें (आंदोलनकारी किसानों को) बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। मेहता ने मोनिका अग्रवाल द्वारा दिल्ली व नोएडा के बीच आवाजाही में हो रही परेशानी को लेकर दायर याचिका में आंदोलनकारी किसान समूहों को पक्षकार बनाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में एक आवेदन दायर करने की अनुमति दे दी और मामले को सोमवार को विचार के लिए रखा दिया है। पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह दिल्ली से सटे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों पर जमे बैठे किसानों को सड़कों से हटने के लिए मनाने के अपने प्रयास जारी रखेगी भले ही किसान इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित पैनल से मिलने के लिए आगे नहीं आए।

तीन राज्यों के राजमार्गों पर डेरा डाले हैं किसान

मालूम हो कि तीन केंद्रीय कानूनों के विरोध में नवंबर से हजारों किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं और इन राज्यों के राजमार्गों पर डेरा डाले हुए हैं। इन मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और कई बिंदुओं पर यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों की यात्रा के समय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पीठ मोनिका अग्रवाल की उस शिकायत पर विचार कर रही है कि लगातार सड़क अवरुद्ध होने और विरोध प्रदर्शन के कारण उसे नोएडा से दिल्ली की यात्रा करने में 20 मिनट के बजाय लगभग दो घंटे लग रहे हैं। एक आईटी कंपनी में काम करने वाली मोनिका ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें काम के लिए दिल्ली और नोएडा के बीच आने-जाने की जरूरत है, लेकिन यात्रा का समय उनके लिए एक बुरा सपना बन गया है।

आम लोगों को नहीं हो कोई असुविधा

23 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार और राज्यों की जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध न करें। कोर्ट ने सड़कों को अवरुद्ध कर किसानों के प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि केंद्र और राज्यों को समन्वय कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि विरोध प्रदर्शन जारी है तो यातायात में किसी भी तरह का व्यवधान न आए, ताकि लोगों के आने-जाने में परेशानी न हो और उन्हें कोई असुविधा न हो।

अमित शाह के बाद अजीत डोभाल से मिले पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह

कैप्टन बोले- कांग्रेस से दूंगा इस्तीफा

चंड़ीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार नए कदम उठाते हुए देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को इस बात का ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं और अब ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते, जहां उनका तिरस्कार किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे। इससे पहले बुधवार शाम को कैप्टन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि कैप्टन भाजपा का दामन भी थाम सकते हैं। हालांकि भाजपा में जाने की बात कैप्टन नकार चुके हैं। वहीं गुरुवार को दोपहर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसके तुरंत बाद अजीत डोभाल की गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात हुई। कैप्टन ने गुरुवार को पंजाब के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिए। कैप्टन पहले भी कह चुके हैं कि पंजाब पाकिस्तान से सटा बॉर्डर स्टेट है, जिसे संभालना सिद्धू या किसी और के बस की बात नहीं है। वहीं राजनीति में उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि तीनों कृषि कानून निरस्त करके व न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देकर पिछले 10 माह से चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे का समाधान किया जाए।

कपिल सिब्बल के आवास पर प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में तकरार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा समेत 'जी-23' समूह के कई नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास के बाहर हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की निंदा की, साथ ही कहा कि इस 'सुनियोजित उपद्रव' में शामिल लोगों के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल और अश्विनी कुमार जैसे नेताओं ने सिब्बल के बयानों को लेकर उन्हें निशाने पर लिया। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन को लेकर कहा कि वह आहत महसूस कर रहे हैं। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, कि मैं असहाय महसूस करता हूं जब हम पार्टी के भीतर सार्थक संवाद आरंभ नहीं कर सकते। मैं उस वक्त भी आहत और असहाय महसूस करता हूं, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने एक साथी और सांसद के आवास के बाहर नारेबाजी किए जाने की तस्वीर देखता हूं। लगता है कि भलाई इसी में है कि व्यक्ति चुप्पी साध कर रखे।

जल्द बुलाई जाएगी सीडब्ल्यूसी की बैठक

चन्नी-सिद्धू बैठक: नाराजगी अभी नहीं हुई दूर?

चंडीगढ़, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान को लेकर पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच गुरुवार की शाम को दो घंटे तक बैठक चली। पंजाब भवन में बैठक को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, हालांकि बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सिद्धू की सभी मांगे मान ली गई है। चन्नी और सिद्धू की इस बैठक के बाद पंजाब में सरकार के बेहतर कामकाज के लिए एक समन्वय समिति गठित होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री के उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी से आम जनता को राष्ट्रीय गौरव की स्मृतियां अपने पास रखने का अवसर मिला- प्रहलाद सिंह पटेल

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिले राष्ट्रीय गौरव से जुड़े उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी हेतु नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही प्रदर्शनी देखी। इस नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की जाएगी।

यह ई-नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित की गई है। जिसमें 1348 उपहारों व स्मृति चिन्हों शामिल किया गया है। स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए उपकरण भी शामिल हैं।

श्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के संरक्षण के लिए मिलने वाले सभी उपहारों को नीलाम करने का फैसला किया है।

श्री पटेल ने कहा कि ई-नीलामी आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार में दी गई यादगार स्मृतियों को रखने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही गंगा नदी के संरक्षण में योगदान भी देगी। उन्होंने इस नेक पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का भाला देखा जिसका बेस प्राइस 1 करोड़ रूपए रखा गया है। ओलंपिक में विजय पताका फहराने वाली पी वी सिंधु का रैकेट जिसका बेस प्राइस 80 लाख रखा गया है। अन्य दिलचस्प कलाकृतियों में अयोध्या राम मंदिर, चारधाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग और अंगवस्त्र की प्रतिकृति शामिल हैं।

सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर फिर किया आगाह, कहा- त्योहारी सीजन में बेहद एहतियात बरतने की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसियां। केरल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में 23 हज़ार के लगभग मामले दर्ज़ किए गए। पिछले हफ्ते दर्ज किए गए कुल मामलों में से 60 फीसद केरल में दर्ज़ हुए। केरल में अभी भी एक लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52 फीसद है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत होगी....

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी देश में हर रोज 15-16 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पाजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। यह लगातार 13वां हफ्ता है जब साप्ताहिक पॉजिटिविटी तीन फीसद से कम रही है। जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, हम सभी से भीड़ से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क का उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वे कोविड को लेकर उचित व्यवहार को बनाए रखते हुए त्योहार मनाएं...

भूषण ने आगे कहा कि महामारी अभी गई नहीं है। मौजूदा वक्त में देश में ऐसे 48 ज़िले है जहां पाजिटिविटी पांच फीसद से ज्यादा है। इसमें से 18 ज़िले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 5 से 10 फीसद के बीच है। ऐसे 30 ज़िले हैं जहां पाजिटिविटी 10 फीसद से ज्यादा है। अभी तक 88 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 64 करोड़ से ज्यादा पहली डोज और 23.70 करोड़ दूसरी डोज शामिल हैं। यही नहीं 99 फीसद स्वास्थ्यकर्मियों को पहला डोज लगाई जा चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100 फीसद लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 18 वर्ष से ज्यादा आयु की जनसंख्या में से 69 फीसद लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है जबकि 25 फीसद लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डा. बलराम भार्गव ने भी लोगों से त्योहारी सीजन में एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मौसम में गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत होगी...

डा. बलराम भार्गव ने कहा कि देश में डेंगू के कुछ स्ट्रेन पाए गए हैं। ऐसे में डेंगू का टीका एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। भारत में इसे लेकर कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। इनमें से कई कंपनियों ने विदेश में अपना पहले चरण का ट्रायल किया है। हम आगे और ट्रायल की योजना बना रहे हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के मसले पर भार्गव ने कहा कि ङ्ख॥ह्र को सारे आंकड़े दे दिए गए हैं। इन आंकड़ों को देखा जा रहा है। डब्ल्यूएचओ इस मसले पर फैसला करेगा।

भार्गव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता पूरी वयस्क आबादी को कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज देने की है। अभी बूस्टर डोज दिए जाने की बात उचित नहीं होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की 86.51 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई है। यही नहीं वैक्सीन की 63.69 लाख से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जानी है।

बिजली मांग बढ़ने के साथ भारत में कोयले की कमी

103 प्लांट्स में आठ दिन से भी कम का कोयला

नई दिल्ली ■ एजेंसी

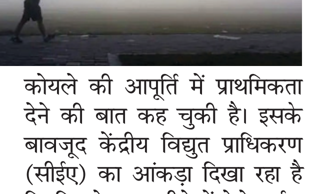

नई रिपोर्ट में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जिन 135 थर्मल पावर प्लांट्स को ट्रैक किया है, 26 सितंबर को उनमें से 103 में 8 दिनों से भी कम का कोयला भंडार बचा हुआ था, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 74 था। भारत में बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने में कोयला आधारित पावर प्लांट्स असमर्थ हो रहे हैं। पिछले दो महीनों में राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई पावर प्लांट्स में कोयले की कमी चल रही है।

जानकार इसकी वजह मॉनसून के चलते कोयला सप्लाई में आई बाधा, भुगतान में गड़बड़ी और बिजली की बढ़ी हुई मांग को बता रहे हैं। केंद्र सरकार कम कोयला भंडार वाले थर्मल पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति में प्राथमिकता देने की बात कह चुकी है। इसके बावजूद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का आंकड़ा दिखा रहा है कि पिछले एक महीने में ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनके पास प्लांट को आठ दिन चलाने के लिए भी पर्याप्त कोयला नहीं है। 10 प्लांट्स में कोयला खत्म सीईए की ओर से जारी की गई नई रिपोर्ट में एजेंसी ने जिन 135 थर्मल पावर प्लांट्स को ट्रैक किया है, 26 सितंबर को उनमें से 103 में 8 दिनों से भी कम का कोयला भंडार बचा था, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 74 था।

कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों से बढ़ी परेशानी

यह आंकड़ा बहुत गंभीर है, क्योंकि इन 88 पावर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 109 गीगावॉट है, क्यों पैदा हुआ संकट कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों में कमी आने के बाद भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। 7 जुलाई को यह अपने शीर्ष 200.57 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई थी। यह मांग अब भी 190 गीगावाट से ऊपर बनी हुई है। जब देश में बिजली की मांग चरम पर थी, तभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे चार बड़े राज्यों ने अपने अंतर्गत आने वाली बिजली इकाइयों के कोयला इस्तेमाल के लिए कोल इंडिया को किए जाने वाले भुगतान में चूक भी कर दी।

सार समाचार

अमेरिका के डलास में एक अपार्टमेंट में विस्फोट, चार दमकल कर्मियों समेत आठ लोग घायल

डलास (अमेरिका)।दक्षिण डलास में एक अपार्टमेंट परिसर में बुधवार सुबह विस्फोट होने से चार दमकल कर्मियों समेत आठ लोग घायल हो गए। इनमें से तीन दमकल कर्मियों की हालत गंभीर है। 'डलास फायर-रेस्क्यू' ने एक बयान में बताया कि दमकलकर्मी दो मंजिला परिसर में प्राकृतिक गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद वहां जांच कर रहे थे। विस्फोट के कारण इमारत के आंशिक रूप से गिरने से ठीक पहले परिसर में गैस रिसाव की गंध आ रही थी। बयान में कहा गया कि आठों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से तीन दमकल कर्मियों की हालत गंभीर है और बाकियों की हालत स्थिर है। विस्फोट के कारण का तत्काल पता नहीं चल पाया है और इस संबंध में जांच जारी है।

दक्षिण कोरिया के साथ 'हॉटलाइन' बहाल करना चाहते हैं उत्तर कोरिया के नेता किम

सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग -उन ने कहा है कि वह अक्टूबर की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के साथ 'हॉटलाइन' बहाल करेंगे। एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को किम के इस बयान की जानकारी दी गई। 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने किम के हवाले से कहा कि इस कदम का लक्ष्य दोनों देशों के बीच शांति की कोरियाई लोगों की इच्छा को पूरा करना है। किम के इस बयान से एक ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने बुधवार को दावा किया था कि उसने एक नई 'हाइपरसोनिक मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केसीएनए ने कहा कि किम ने यह बयान देने के साथ ही दक्षिण कोरिया से अपील की कि वह अपने ''अनुचित दोहरे व्यवहार'' और ''शत्रुतापूर्ण नीतियों'' को त्याग दे। किम ने यह भी कहा कि अमेरिका की ''शत्रुतापूर्ण नीतियां'' और ''सैन्य खतरे'' अब भी बने हुए हैं और उसका वार्ता का हालिया प्रस्ताव केवल इस शत्रुता को छुपाने की कोशिश है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधो में ढील और अन्य रियायतें देने के लिए राजी कर पाए।

मेक्सिको ने 70 हाउतियन प्रवासियों को घर वापस भेजा

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको ने प्रवासी संकट के बीच 70 हाउतियन प्रवासियों को उनकी राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस वापस भेजा, यह हाउतियन संयुक्त राज्य की सीमा पर आते थे। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको के विदेश मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय ने एक संयुक्त बयान में बताया कि समूह में 41 पुरुष, 16 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल हैं। बयान में कहा, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित आव्रजन के प्रति प्रतिबद्धता, मानवाधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान और सुरक्षा की पुष्टि की जाती है। मेक्सिको के विदेश मंत्री मासेर्लो एब्रार्ड ने कहा कि उनके देश ने उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने की पेशकश की थी जिन्होंने इसे अन्य देशों में प्राप्त नहीं किया था।

ट्यूनीशिया में पहली बार महिला बनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैस सईद ने किया नियुक्त

ट्यूनिस। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने बुधवार को राष्ट्रपति पद के अनुसार नई सरकार बनाने वाली नजला बोडेन रोमधाने को अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नए सरकार के प्रमुख को संबोधित करते हुए सईद ने घोषणा की कि देश जिस असाधारण स्थिति से गुजर रहा है, उसे देखते हुए मैंने आपको एक नई सरकार बनाने का काम सौंपने का फैसला किया है। सईद ने कहा, आप हमारे देश के इतिहास में सरकार की पहली महिला मुखिया हैं। सईद ने कहा, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने और अराजकता को खत्म करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप पिछले असाधारण उपायों के प्रावधानों के अनुसार आने वाले घंटों या दिनों में सरकार के गठन का प्रस्ताव देने में कामयाब होंगे। सईद ने कहा कि नई सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के अधिकार की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। 1958 में जन्मी, नव नियुक्त प्रधानमंत्री ट्यूनिस के नेशनल इंजीनियरिंग स्कूल में एक अकादमिक थी और ट्यूनीशियाई उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में विश्व बैंक कार्यक्रम निष्पादन अधिकारी के पद पर भी रह चुकी हैं।

पुतिन, एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

मोस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को सोची में अपने तुर्की समकक्ष रेसेप तईप एर्दोगन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर सहयोग पर चर्चा की। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूसी-तुर्की सहयोग सफल रहा है, जो सीरिया और लीबिया पर स्थिति के समन्वय के उद्देश्य से किए गए प्रयासों की ओर इशारा करता है। उन्होंने नागोर्नो-कराबाख में युद्धविराम की निगरानी के लिए रूसी-तुर्की केंद्र के काम का सकारात्मक मूल्यांकन किया, और कहा कि इसने क्षेत्र में स्थिरता और सुलह को बढ़ावा देने का काम किया। रूसी नेता ने तुर्की स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के सफल काम पर भी जोर दिया, जिसने यूरोपीय गैस बाजार में अशांत स्थिति के बीच काम करना जारी रखा है। दोनों नेताओं ने कहा कि तुर्की प्रांत मेर्सिन में अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर योजना के अनुसार काम किया जा रहा है। एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच सैन्य, व्यापार, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के संबंध में प्रगतिशील विकास का उल्लेख किया और कहा कि सीरिया में शांति काफी हद तक मास्को और अंकारा के बीच सहयोग पर निर्भर करती है।

चीन का बीआरआई प्रोग्राम 42 देशों के लिए बना जी का जंजाल, 385 अरब डॉलर के कर्ज के नीचे दबे सभी

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन का पुराना फार्मूला है इन्वेस्टमेंट और व्यापार के लुभावने वादे। श्रीलंका हो या मालदीव पाकिस्तान हो या नेपाल, इन देशों में खूब इनवेस्ट करता है और तरक्की के सपने बेचता है और फिर इसी कर्ज की राह अपने सामरिक हित साधता है। चीन का मकसद बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिये पूरी दुनिया को चीन से जोड़ने का है। इसके लिए वो कई देशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके तहत उसने सलाना 85 अरब डॉलर के करीब खर्च किए हैं। चीन की महत्वकांक्षा अब 42 देशों के लिए मुसबीत बनती जा रही है। अब इन देशों को चीन के 385 अरब डॉलर की चिंता सताने लगी है। एक स्टडी के अनुसार इन देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी के 10प्र. से अधिक पहुंच गया है।

AidData द्वारा आज जारी अध्ययन को 'बैंकिंग ऑन बेल्ट एंड रोड पर- 13,427 चीनी विकास परियोजनाओं का वैश्विक डेटासेट' नाम दिया गया है। इसके मुताबिक बीआरआई की 35प्र. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार घोटालों मजदूर हिंसा, पर्यावरण असुरक्षा और जनविरोध जैसी बड़ी कार्यान्वयन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआरआई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पटरी पर उचारने में औसतन 1047 दिन का समय लगता है। इसकी तुलना में बीआरआई के इतर चीनी सरकार द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं में स्थिति काफी बेहतर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मेजबान सरकारें 'भ्रष्टाचार और अधिक कीमतों की चिंताओं के साथ-साथ सार्वजनिक भावना में बड़े बदलाव के कारण हाई-प्रोफाइल बीआरआई परियोजनाओं को प्रभावित कर रही हैं, जिससे चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना मुश्किल हो गया है। चीन दूसरे देशों को मदद के बजाय लोन देना पसंद करता है। बीआरआई में उसका लोन-टु-ऐड रेश्यो 31:1 है जो किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत अधिक है। एशिया बेस्ड एकेडमिक राइटर रिचर्ड हेडेरियन का कहना है कि बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से 21 वीं सदी की भू-राजनीति की धुरी बनता जा रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक आधिकारिक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अब से 2040 तक दुनियाभर में इन्फास्ट्रक्चर के विकास के लिए 94 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। यह चीनी धन के लिए दुनिया की भूख की व्याख्या करता है, साथ ही साथ क्यों देश बीआरआई की कमियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं।

इजराइल: यरुशलम में इज़राइल पुलिस ने अधिकारियों पर हमला करने वाली महिला को गोली मारी

यरुशलम। इज़राइली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अधिकारियों ने उस फलस्तीनी महिला को गोली मार दी है, जिसने पूर्वी यरुशलम की ओल्ड सिटी में उन्हें कथित तौर पर चाकू मारने की कोशिश की थी। महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया कि महिला शहर के पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार (जिसे मुस्लिम, अल-अक्सा परिसर और यहूदी, टेंपल माउंट के रूप में जानते हैं) पर अधिकारियों के पास आई थी।

पुलिस ने कहा, '' महिला ने पास पहुंचते ही एक चाकू निकाला और अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की। चिकित्साकर्मियों ने महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया।'' फलस्तीनियों ने हाल के वर्षों में यरुशलम और वेस्ट बैंक में इज़राइल के सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई बार कार से टक्कर मारने की कोशिश की, गोलीबारी की और चाकू से भी हमले किए हैं। वर्ष 1967 के युद्ध में इज़राइल ने पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था।

संकट में सीपीईसी परियोजना, पिछले 3 साल के दौरान नहीं हुआ काम

इस्लामाबाद/नई दिल्ली (एजेंसी)।

पाकिस्तान की योजना पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष सलीम मांडवीवाला ने हाल ही में कहा है कि चीनी राजदूत और कंपनियों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजनाओं पर काम की धीमी गति के बारे में शिकायत की है।

उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, वे रो रहे हैं। चीनी राजदूत ने मुझसे शिकायत की है कि आपने (पाकिस्तान) सीपीईसी को नष्ट कर दिया है और पिछले तीन वर्षों में कोई काम नहीं किया गया है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से चीनी बहुत नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2015 में शुरू होने के बाद से देश में 77 सीपीईसी परियोजनाओं में से सिर्फ 15 ही पूरी हो सकी हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के योजना एवं विकास मंत्री असद उमर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान सीपीईसी का पहला चरण ही पूरा कर सकता है और यह दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है।

सीपीईसी को धीमा करने की धारणा को दूर करने के लिए हाल ही में एक जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान पीटीआई सरकार के कार्यकाल के दौरान कॉरिडोर परियोजनाओं पर प्रमुख काम पूरा हो गया है। हालांकि, उमर ने यह भी माना कि सीपीईसी के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के विरोध और अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के कारण

देश में सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि सीपीईसी पर विकास को बड़ी वैश्विक शक्तियों द्वारा घृणा के साथ देखा गया है, जो देश में असंतोष फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की अनिश्चित स्थिति के कारण भी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, इसलिए न केवल सुरक्षा चुनौतियां हैं, बल्कि ये एक ऊंचे स्तर पर हैं।

सीपीईसी चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों में देश के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को नवीनीकृत करना है। 2015 में, चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) परियोजना की घोषणा की थी, जिसकी लागत 60 अरब डॉलर से अधिक बताई गई है। सीपीईसी के साथ, बीजिंग का लक्ष्य अमेरिका और भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और मध्य और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना है।

सीपीईसी पाकिस्तान के दक्षिणी ग्वादर बंदरगाह (कराची से 626 किलोमीटर पश्चिम में) को अरब सागर पर चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ेगा। इसमें चीन और मध्य पूर्व के बीच संपर्क में सुधार के लिए सड़क, रेल और तेल पाइपलाइन लिंक बनाने की योजना भी शामिल है। सीपीईसी बीआरआई पहल का हिस्सा है, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) पर नियंत्रण पाने के लिए चीन की भू-रणनीति के रूप में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत और इसकी ऊर्जा आपूर्ति को घेरने के साथ ही मध्य पूर्व और मध्य एशियाई क्षेत्र तक पहुंच का विस्तार करना भी है।

हालांकि, भ्रष्टाचार, सुरक्षा लागत और पाकिस्तान के कर्ज संबंधी तनाव के मुद्दों ने चीनी रुख को तेजी से प्रभावित किया है और इसे सीपीईसी में निवेश करने से अनिच्छुक बना दिया है, जिसने चीन-पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती को प्रभावित किया है। 14 जुलाई को उत्तरी पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा के दसू में नौ चीनी कामगारों की हत्या कर दी गई थी। चीनी और पाकिस्तानी श्रमिकों को ले जा रही एक बस में विस्फोट हुआ था, जो सीपीईसी के हिस्से के रूप में चीन द्वारा बनाए जा रहे एक जलविद्युत बांध की साइट पर हुआ था। विस्फोट के बाद से परियोजना पर काम रोक दिया गया है और इस्लामाबाद को पाकिस्तान में इसकी परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में बीजिंग को आश्वस्त करने के लिए बहुत पीड़ा हो रही है।

तालिबानियों से सामना करने को तैयार है यह महिलाएं, किसी भी हाल में नहीं रोकेगी अपना काम

काबूल।(एजेंसी)।

अफगानिस्तान में तालिबान की हुकुमत के बाद से देश की महिलाओं की हालत काफी दयनीय है। महिलाओं के कामाकाज में रोक लगाई जाने के बीच तालिबान के हेरात प्रांत में भगवा मसाला कारोबार में शामिल अफगान महिलाओं ने यह साफ कर दिया है कि, तालिबान के डर से उन्हें नजरबंद नहीं किया जाएगा। वह लंबे समय से कारोबार कर रहे है और सत्ता में आने के बाद तालिबान के डर से अफगान महिलाएं किसी भी हाल में अपना काम नहीं रोकेगी।

साल 2006 तक सफी अट्टाई ने हेरात के पश्तून जरघन जिले में 25 हेक्टेयर भूमि पर केसर मसाला कारखाना स्थापित किया था। इसी भूमि पर केसर के फूल उगाए जाते हैं और कारखाने में दुनिया का सबसे महंगा %केसर क्रोकस% मसाला बनाया जाता है। अट्टाई की कंपनी में काम करने वाले लगभग सभी लोग महिलाएं हैं। संगठन की एक हजार से ज्यादा अफगान

महिलाएं केसर के फूल तोड़ने में शामिल हैं। इन अफगान महिलाओं का भविष्य 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान शासन की शुरुआत के बाद से ठहर गया है। कई लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अट्टाई 20 साल से बनी हुई जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, हम आज बड़ी मुश्किल से इस जगह पर आए हैं,। हम किसी भी हाल में घर पर नहीं बैठेंगे। नई अफगान सरकार में महिला प्रतिनिधि होने की बात तो दूर, तालिबान ने अभी तक लड़कियों को स्कूल या कॉलेज जाने की स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। 20 साल की लड़ाई और कड़ी मेहनत के बाद अफगान महिलाओं ने अपनी जमीन खुद बनाई है। उस जमीन पर तालिबान दोबारा कब्जा कर रहा है।

बेसबॉल के प्रेमी हैं जापान के होने वाले नए पीएम फूमिओ किशिदा, सामने होंगी कई चुनौतियां

नई दिल्ली (एजेंसी)।

जापान की सत्ता से योशिहिदे सुगा का हटना बिल्कुल साफ हो गया है और इस बीच अब विदेश मंत्री फूमिओ किशिदा जापान की कुर्सी संभाल सकते है। पीएम मद की दौड़ में फूमिओ किशिदा को देखा जा रहा है और उन्होंने सत्तारुढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव भी जीत लिया है।

पीएम पद संभालने के बाद किशिदा के सामने आएंगी ये चुनौतियां

जापान के पीएम की कुर्सी संभालते ही फूमिओ किशिदा के सामने कई चुनौतियां होंगी। एक जगह उन्हें कोरोना महामारी की मार झेल रही जापान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर सोचना होगा तो दूसरी और देश के क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते और गंठबंधन बनाने की चुनौती होगी।

कौन है फूमिओ किशिदा

फूमिओ किशिदा सत्तारूढ पार्टी के निवर्तमान नेता और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह आएंगे। आपको बता दें कि जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने पिछले साल सितंबर में पद संभाला था और अब वह यह पद छोड़ रहे है। 64 साल के फूमिओ किशिदा 1993 में राजनिति में आने से पहले बैंक में काम करते थे। बैसबॉल के शौकीन रखने वाले किशिदा ने लॉ की पढ़ाई के लिए भी एंट्रेस दिया था लेकिन इसमें वह 3 बार फेल हुए।किशिदा ने कोरोना महमारी के समय भी जनता की राय के लिए सुझाव पेटी भी रखवाई थी।2012 से 2017 के बीच किशिदा का राजनिति सफर एक विदेश मंत्री के रूप में रहा।शिंजो आबे नजब पीएम पद छोड़ा था तब भी वह पीएम के पद के लिए कोशिश कर रहे थे।

अफगानिस्तान से आईएस को उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान ने छेड़ा अभियान

काबुल।(एजेंसी)।

तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से राज स्थापित करने के बाद अब अपने पुराने दुश्मन इस्लामिक स्टेट (आईएस) को जड़ से खत्म करने का मन बना लिया है। इसके लिए तालिबान ने एक अभियान की शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने काबुल में मौजूद स्थानीय शासा और नंगरहार पर कार्रवाई करने का मन बनाया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईएस के खिलाफ शुरू किए गए अभियान की शुरुआत नंगरहार से होगी। दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान के कई लड़ाकों को निशाना बनाया जा चुका है। जलालाबाद के एक स्थानीय गैस स्टेशन पर खड़े तालिबान के वाहन पर बंदूकधारियों ने गोलियां चलायीं जिससे दो लड़ाकों एवं गैस स्टेशन परिचारक की मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई बार तालिबानियों को निशाना बनाया जा चुका है।

20 साल बाद स्थापित किया राज

तालिबान की 15 अगस्त के दिन काबुल में एंट्री के साथ ही अमेरिकी समर्थित अशरफ गनी सरकार गिर गई और चारों तरफ अफरातफरी का महौल था। इसके कुछ हफ्तों के बाद तालिबान ने सरकार गठित कर ली। हालांकि सरकार गठन करने के बाद भी कुछ सरकारी कार्यालय अभी तक नहीं खुले हैं। 20 साल बाद तालिबान को अफगानिस्तान की गद्दी मिली। इसके बावजूद तालिबान नहीं बदला।

तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही काबुल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कई बार तालिबान और आईएस के बीच में भिड़ंत हुई।

आईएसआई के साथ तालिबान के रिश्ते पर बंद कमरों में चर्चा हो: अमेरिका रक्षा मंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सीनेटरों से कहा है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संबंधों पर केवल बंद कमरों के भीतर ही चर्चा की जा सकती है।

उनके साथ दो शीर्ष जनरल भी मौजूद थे। ऑस्टिन ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा, ''पाकिस्तानके बारे में एक गहन बातचीत शायद यहां एक बंद कमरे में उचित होगी।''

उनके दो जनरलों, यूएस ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल मार्क मिले और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने भी यही कहा। मिले ने कहा, ''मैंने पिछले कुछ वर्षों में और हाल ही में पाकिस्तानियों के साथ कई बार बातचीत की है और मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध तेजी से जटिल होते जा रहे हैं।''

आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अगस्त के आखिरी सप्ताह में अघोषित दौरे पर काबुल गए थे और तालिबान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। अगस्त के मध्य में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा करने के बाद से वह अफगानिस्तान का दौरा करने वाले पहले उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी थे।

मैकेंजी ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के परिणामस्वरूप तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी जटिल होते जा रहे हैं। सीनेटर जीन शाहीन ने पूछा, ''क्या हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह संबंध और अधिक जटिल हो जाएगा? क्या हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और उस क्षमता के बारे में चिंतित हैं कि आतंकवादी समूह उन हथियारों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं?

सीनेटर गैरी पीटर्स ने पाकिस्तान के साथ साझा हितों के बारे में पूछा तो ऑस्टिन ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक प्रमुख साझा हित अफगानिस्तान या क्षेत्र में मानवीय आपदा को रोकना है। और इसलिए, मुझे लगता है कि हम उस हित को साझा करना जारी रखेंगे।

केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जन-भागीदारी को देगी बढ़ावा

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)। दिल्ली में केजरीवाल सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जन-भागीदारी को बढ़ावा देगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरडब्ल्यूए-एनजीओ, ईको क्लब के साथ बैठक की है। गोपाल राय ने कहा कि सरकार दिन-रात प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। प्रदूषण पैदा न हो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना होगा। आरडब्ल्यूए-एनजीओ , ईको क्लब ने सुझाव दिया है कि रेड लाईट ऑन, गाड़ी आफ ड्राईव का आगे जारी रखा जाए। आरडब्लूए अपने स्तर पर कार पुलिंग को प्रमोट करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लोग प्रदूषण को कम करने संबंधी सुझाव ग्रीन वॉर रूम एट जी मेल पर दे सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदूषण के विरूद्ध अभियान में जन-भागीदारी को बढ़ाया जाए।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को कम करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरडब्लूए, एनजीओ और इकोक्लब के सदस्यों के साथ बैठक की। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में इससे निपटने के लिए सुझाव मांगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य यह था कि सरकार का काम प्रदूषण हो जाने के बाद शुरू होता है। सरकार दिन-रात प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदूषण पैदा ही न हो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए

लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भावना को विकसित करना होगा। जन भागीदारी द्वारा इसे करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक की सभी स्टडीज बता रही हैं कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण बढ़ता है। पहली वजह दिल्ली के अंदर से प्रदूषण पैदा होता है, जिसमें वाहन प्रदूषण, डस्ट प्रदूषण, बायोमास प्रदूषण होता है। दूसरा जो प्रदूषण बाहर से आता है। सरकार प्रदूषण को पैदा होने से रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही हैं। लेकिन इस प्रदूषण को हम सब दिल्ली वाले मिलकर पैदा करते है। यह छोटा-छोटा मिलकर पूरी दिल्ली में बड़ा प्रदूषण बनता है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि इसे कैसे एक जन आंदोलन बनाया जाए। ताकि, हम जो अपने हिस्से का प्रदूषण पैदा करते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं।

आप ने निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा ने साउथ एमसीडी में टैक्स की बढ़ी हुई दरों को कम करने की घोषणा की है। जबकि कमिश्नर ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। इससे पहले उन्होंने नॉर्थ एमसीडी में भी ऐसी ही घोषणा की थी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। भाजपा निगम सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी घोषणाएं करता है। आम आदमी पार्टी ने इस घोषणा को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। एमसीडी प्रभारी ने कहा कि जब तक कमिश्नर यह आदेश लागू नहीं करता है तब तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी और व्यापारियों के हक में आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में बैठी भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ भ्रष्टाचार करने और झूठ बोलने का काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा निगम ने नॉर्थ एमसीडी में टैक्स की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की घोषणा की थी। यह घोषणा भी उन्होंने आम आदमी पार्टी और व्यापारियों के कड़े विरोध के चलते की थी।

दक्षिणी निगम की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग की शुरूआत

नई दिल्ली,(रविशंकर तिवारी)। दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सुर्यान ने गुरूवार को द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन पर पहली फास्टैग आधारित पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष स्थायी समिति कर्नल बी.के. ओबरॉय, स्थानीय पार्षद एवं स्थायी समिति के सदस्य राजदत्त गहलोत, आयुक्त ज्ञानेश भारती, अतिरिक्त आयुक्त ए.ए. ताजीर, उपायुक्त नजफगढ़ क्षेत्र भूपेश चौधरी, प्रमुख अभियंता पी.सी. मीणा, उपायुक्त प्रेम शंकर झा सहित दक्षिणी निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने फास्टैग आधारित नई पार्किंग व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि यह सुविधा प्रथम बार निगम द्वारा अपने नागरिकों को दी जा रही है जिसके बाद नागरिकों को पार्किंग शुल्क का भुगतान करने में सुगमता होगी। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी निगम ने पार्किंग शुल्क का भुगतान आर. एफ. आई. डी फास्टैग से लेने का निर्णय किया है। इसके लिए दक्षिणी निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधीन कंपनी आई.एच.एम.सी.एल को द्वारका सेक्टर 14 स्थित पार्किंग का शुल्क एकत्रित करने की अनुमति दी है। ज्ञानेश भारती आयुक्त दक्षिणी निगम ने फास्टैग आधारित पार्किंग शुल्क वसूली की नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि दक्षिणी निगम ने नागरिकों की सहूलियत के लिए पहली बार आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही गाड़ी पार्किंग से बाहर निकेलगी वैसे ही उसके शीशे पर लगे फास्टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क कट जायेगा। इस व्यवस्था के लागू होने पश्चात् नागरिकों को पार्किंग शुल्क का भुगतान करने के लिए नागरिकों को खुले पैसे रखने एवं नकदी में भुगतान करने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

संक्षिप्त खबर

दक्षिणी निगम के महापौर ने आप पार्षद के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

नई दिल्ली। दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेम चौहान के खिलाफ सोशल मीडिया और आम जनता में बिना किसी तथ्यों मानहानि बयान देने पर कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेम चौहान ने मुकेश सुर्यान के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विधिवत निर्वाचित महापौर हैं। प्रेम चौहान निगम के आगामी चुनाव के लिए महापौर की छवि खराब करना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ हासिल करने की दृष्टि से उनके बयान झूठे और बिना किसी सार के हैं। प्रेम चौहान ने आरोप लगाया कि एक विज्ञापनदाता से रिश्वत ले रहे है इसलिए निगम डीएनडी फ्लाई वे पर अवैध यूनीपोल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। प्रेम चौहान ने एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया और महापौर पर झूठे आरोप लगाए। वे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विधिवत निर्वाचित महापौर के खिलाफ बिना किसी आधार और सच्चाई के आरोप लगाते हुए अपनी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर रहे है।

विपुल रे ने आईईईमए के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। भारतीय विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैकक्चरर्स असोसिएशन आईईईएमए ने मौजूदा वर्ष 2021-22 के लिए एलमेक्स कंट्रोल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विपुल रे की आईईईएमए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। श्री रे ने असोसिएशन की हुई सालाना आम बैठक में पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा अन्य ऑफिस पदाधिकारियों, बिरला कॉपर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ रोहित पाठक और स्टेलमेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री हमजा अर्सीवाला ने भी वर्ष 2021-22 के लिए उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। विपुल रे ने आईईईएमए के बारे में अपनी विजन और प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए कहा की भारत ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर भारतीय इलेक्ट्रिकल और उसे जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के सामने कई अवसर हैं।

वार्नर म्यूजिक और जेटसिंथेसिस ने की रणनीतिक साझेदारी

नई दिल्ली। यूएस स्थित मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय मनोरंजन और रिकॉर्ड लेबल समूह वार्नर म्यूजिक ग्रुप डब्ल्यूएमजी और नए युग की डिजिटल मनोरंजन और प्रौद्योगिकी कंपनी जेटसिंथेसिस एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करने के लिए एक साथ आए हैं। इस साझेदारी के साथ, जेटसिंथेसिस संगीत लेबल लाइसेंसिंग और अधिग्रहण, कलाकार प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, संगीत में मूल सामग्री निर्माण, स्माल वीडियो और फिल्मों के साथ-साथ मोबाइल गेमिंग और एस्पोर्ट्स से संबंधित सभी चीजों के लिए डब्ल्यूएमजी का भारत में आधिकारिक भागीदार बन गया है। साथ ही, जेटसिंथेसिस , जो गेमिंग, डिजिटल मनोरंजन और रुचि-आधारित सोशल कम्युनिटी प्लेटफार्मों में वैश्विक स्तर पर है, आगामी तीन वर्षों में भारतीय मनोरंजन क्षेत्र में 200 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। राजन नवानी, वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, जेटसिंथेसिस ने कहा की हम वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ जुड़ने और भारतीय बाजार के लिए उनके भागीदार बन उत्साहित हैं। जब मनोरंजन की बात आती है तो बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और व्यवहार पर मजबूत पकड़ के साथ, हम एक साथ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर और नए मनोरंजन की बढ़ती मांग को पूरा कर उद्योग के प्रसार में योगदान करने का लक्ष्य रखते हैं।

रोहिणी अदालत में गोली बारी के बाद काला जठेड़ी ने सुरक्षा में पेशी की लगाई गुहार

(प्रवीण कुमार सिंह)

नई दिल्ली । पिछले सप्ताह रोहिणी कोर्ट में हुई गोली बारी के बाद कथित गैंगस्टर काला जठेड़ी को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। जठेड़ी की तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर की गई है। काला जठेड़ी ने कहा की उसे जब कब भी अदालत में पेशी के लिए लाया किया तो उसे हाथो मे हथकड़ी लगाकर पेश किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के जठेड़ी को अपने साथ फर्जी मुठभेड़ का डर सता रहा है। इसीलिए उसने पटियाला हाउस अदालत का रुख किया है। अदालत ने इस मामले में जठेड़ी की याचिका पर पुलिस को उसकी सुरक्षा के पक्के इंतजाम करने को कहा है। अदालत में कला जठेड़ी के वकील विशाल चौपड़ा की ओर से दायर अर्जी में यह भी कहा है की उसे जूते भी बिना लेस के पहनाए जाए।

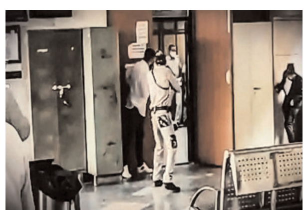

> ट्रांजिस्ट रिमांड पर भी यही सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। जब भी काला जठेड़ी को दिल्ली के बाहर पुलिस हिरासत में लेकर जाया जाएगा, तो दिल्ली की अदालत के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगाः **अदालत**

अदालत ने काला जठेड़ी की अर्जी पर जेल अधिकारियों ओर सम्बंधित पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए है। काला जठेड़ी की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अदालत ने कहा है कि ट्रांजिस्ट रिमांड पर भी यही सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। जब भी काला जठेड़ी को दिल्ली के बाहर पुलिस हिरासत में लेकर जाया जाएगा, तो दिल्ली की अदालत के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ताकि किसी भी राज्य की पुलिस यह न बोल पाए की काला ने पुलिस कस्टडी से भगाने की कोशिश की। इसी की आड़ में उसको मार दिया जाए। ज्ञात रहे कि बहरहाल काला जठेड़ी राजस्थान पुलिस की हिरासत में है। काला जठेड़ी को पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उसकी महिला साथी रिवाल्वर रानी के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस अभियान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी शामिल थी। जठेड़ी कई राज्यों का नामी अपराधी है। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जोकि पटियाला हाउस अदालत में लंबित है।

मानव तस्करी व दुष्कर्म की शिकार महिला ने मांगा 19 लाख का मुआवजा, हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली । मानव तस्करी और दुष्कर्म का शिकार हुई महिला द्वारा 19 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग और कानूनी सेवा प्राधिकरण से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई नौ दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।महिला ने याचिका दायर करके कहा कि वह मेघालय के एक गांव में रहती है और गरीब परिवार से है। नौकरी दिलाने के बहाने उसका चचेरा भाई 20 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी दिलाने का झांसा देकर जनवरी 2020 में उसे दिल्ली लेकर आया था जोकि अन्य लोगों के साथ मिलकर मानव तस्वरी का गिरोह चलाता था। जब वह यहां पहुंची तो उसे एक फ्लैट में ले जाया गया और वहां एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसे कई लोगों को बेचा गया और उन्होंने भी उसका यौन शोषण किया। फरवरी 2020 में वह भागने में सफल रही थी और एक दोस्त की मदद से मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से संपर्क कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा कि स्पष्ट शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा दुष्कर्म की धारा में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर वह चौक गई थी।

महिला ने दावा किया कि उसने फरवरी-2021 में 19 लाख रुपये के मुआवजा की मांग करते हुए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना और महिलाओं के लिए मुआवजा योजना/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराध-2018 के तहत मुआवजे के लिए एक आवेदन दायर किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजा गया था। हालांकि, अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वहीं, गंभीर शारीरिक विकृति से पीड़ित 23 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की मांग वाली महिला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लेडी हार्डिंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने महिला की जांच करने और तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।

महिला ने कहा कि वह 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति चाहती है। अधिवक्ता स्नोहा मुखर्जी के माध्यम से याचिका दायर करने वाली महिला ने बताया कि हाल ही में कराए गए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि उसका भ्रूण गंभीर शारीरिक विकृति से पीड़ित है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अन्य समस्याओं के अलावा खोपड़ी की हड्डी नहीं है। नियम के तहत गर्भधारण की अवधि 20 सप्ताह से अधिक होने की स्थिति में गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली कांग्रेस ने जी-23 के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा, कैप्टन, सिद्धू, सिब्बल और पायलट को सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली । कांग्रेस आलाकमान को लगातार घेर रहे जी 23 नेताओं के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के सुर भी बदलने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन ने भी बाजू चढ़ा ली हैं। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ पार्टी नेता सचिन पायलट का बाकायदा नाम लेकर उन पर निशाना साधा है।

बृहस्पतिवार को कुछ पत्रकारों से बातचीत में जयकिशन ने कहा कि उक्त सभी नेताओं को कांग्रेस ने राष्ट्रीय पहचान दी है। ऐसे भी अनेक नेताओं को पार्टी ने बुलंदियों पर पहुंचाया जो एमएलए तक का चुनाव जीतने में सक्षम नहीं थे। इसके बावजूद यह नेता आज आलाकमान को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। जयकिशन ने ऐसे सभी नेताओं को सलाह दी है कि पहले वे अपने गिरेबान में झांके और देखें कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया है और कितना योगदान दिया है।

गांधी परिवार के खिलाफ अंगुली उठाने वालों को दी नसीहत– जयकिशन ने कहा कि जिस गांधी परिवार पर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी आज अंगुली उठा रहे हैं, उसकी कुर्बानियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सियासत में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिलकर चलने के बजाए आपस में ही उलझना शुरू कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी नेताओं की आज जो पहचान है, वह भी कांग्रेस की ही बदौलत है।

मालूम हो कि कुछ समय पूर्व अनिल चौधरी ने भी सिब्बल पर निशाना साधा था। ट्वीट करके उन्होंने तो सिब्बल को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसी भी जिम्मेदारी को संभालने का आफर तक दे दिया था ताकि उन्हें एहसास हो सके कि संगठन के लिए काम करना और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करना आलोचना करने से कहीं अधिक मुश्किल है।

दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों ने थाने में काटा जमकर बवाल, पुलिसकर्मियों को पीटा; करना पड़ा हवाई फायर

नई दिल्ली। मोहन गार्डन थाना में अफ्रीकी नागरिकों ने जमकर बवाल काटा। आरोपित अफ्रीकी नागरिक हाथ में डंडे, राड, पत्थर, ईट लेकर आए और सामने में उन्हें जो भी पुलिसकर्मी नजर आया, उसे पीटते चले गए। इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वे थाना परिसर में तोड़फोड़ करने लगे। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने लगे। जो कुछ भी उन्हें नजर आया, उसे तोड़ डाला। जो भी पुलिसकर्मी इन्हें शांत करने की कोशिश करता, वह मुंह की खाता। इनका गुस्सा शांत होने के बजाय और उग्र होता चला गया। एक एएसआइ व दो कांस्टेबल को तो ये घेरकर काफी देर तक पीटते रहे।

इस बीच कुछ आरोपित तो इन्हें मारने पर अमादा थे और दूसरों को इन्हें मारने के लिए उकसा रहे थे। सामने मौत आता देखकर पुलिसकर्मी को हवा में गोली चलानी पड़ी, तब किसी तरह पुलिसकर्मी इनके घेरे से बाहर निकल पाए। हालांकि इसके बाद पुलिसकर्मी थोड़े संभले और आठ अफ्रीकी नागरिकों को काबू कर दबोच लिया। इसके बाद भी करीब एक घंटे तक मोहन गार्डन थाना परिसर में इनका उत्पात चलता रहा। पत्थराबाजी व तोड़फोड़ में ये जुटे रहे। बाद में जब मौके पर कई थानों की पुलिस एकत्रित हुई तब मामला शांत हुआ।उधर खाकी की साख जब धूमिल हो गई तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अभी तक इस मामले में 53 अफ्रीकी नागरिकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभी और भी गिरफ्तारियों की बात पुलिस अधिकारी बता रहे हैं।

यह मामला 26 सितंबर की देर रात का है। दरसअल द्वारका मोड़ स्थित एक अस्पताल में एक अफ्रीकी नागरिक को बेसुध अवस्था में लाया गया। अस्पताल में इसे मृत घोषित कर दिया गया। जब चिकित्सक इसकी एमएलसी तैयार करने लगे तब अफ्रीकी नागरिक इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इस बीच मामला अशांत होने पर अस्पताल से पुलिस को इस मौत की जानकारी मिली। जब पुलिस यहां जानकारी लेने पहुंची तो अफ्रीकी नागरिक अचानक भड़क उठे। यहां से करीब सौ की तादाद में अलग अलग वाहनों पर सवार होकर ये मोहन गार्डन थाना पहुंचे और वहां बवाल काटना शुरू कर दिया।

अब कार्रवाई हुई शुरू– मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में आजकल पुलिसकर्मियों की टोली घर घर जाकर ऐसे अफ्रीकी नागरिकों के बारे में पता लगा रही है जो अवैध रूप से यहां रह रही है। पुलिस ऐसे अफ्रीकी नागरिकों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ, उन्हें अपना मकान किराया देने वाले मकानमालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर रही है। रोजाना मोहन गार्डन थाना में ऐसे दो से तीन मामले दर्ज हो रहे हैं। क्षेत्र के लोग पुलिस की इस कार्रवाई को विलंब से उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। बता दें कि मोहन गार्डन, उत्तम नगर, तिलक नगर, बिंदापुर, महावीर एंक्लेव, निहाल विहार सहित आसपास स्थित कालोनियों में बड़ी संख्या में अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। पुलिस का कहना है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो नशीले व मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। समय समय पर कार्रवाई करके ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार भी करती रही है।

दिल्ली में बिजली की नई दरें घोषित, ई वाहन वालों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

नई दिल्ली । कोरोना संकट दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने लगातार दूसरे वर्ष बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया गया है। साथ ही इस वर्ष भी स्थायी शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी। वहीं, दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए पुराने बिजली संयंत्रों के साथ बिजली खरीद समझौते को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हरित बिजली को बढ़ावा देने के दिशा में कदम उठाए गए हैं। एक अक्टूबर से बिजली की नई दरें लागू होंगी।

महंगी बिजली खरीदने से परहेज

लंबे इंतजार के बाद डीईआरसी ने वर्ष 2021-22 के लिए बिजली की दरें घोषित कर दी है। आयोग ने निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिजली की दरें बढ़ाने की मांग को नकारते हुए उपभोक्ताओं के हक में फैसला किया है। दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिल

सके इसके लिए दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) ने दादरी-एक, अंता गैस, औरेया गैस, दादरी गैस, फरक्का, कहलगांव-एक और ऊंचाहार-दो बिजली संयंत्रों से बिजली खरीद समझौता खत्म करना चाहती हैं। इन संयंत्रों से दिल्ली को 1050 मेगावाट बिजली मिलती है और इसकी दरें ज्यादै हैं। डीईआरसी ने डिस्काम की इस मांग को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सामने उठाया है।

दिल्ली में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को सस्ती एपीएम (प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र) गैस नहीं मिलती है। इससे इन संयंत्रों का बिजली उत्पादन लागत ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सामने यह मामला उठाया है। दिल्ली के उपभोक्ताओं व पर्यावरण के हित में गैस आधारित संयंत्रों को एपीएम गैस उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

ई वाहन चार्ज करने के लिए सस्ती बिजली– राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो वर्ष ई वाहन को चार्ज करने के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। यह रियायत इस वर्ष भी जारी रहेगी। चार्जिंग स्टेशन पर ई-रिक्शा व अन्य ई वाहनों की बैटरी लोग सस्ती दरों पर चार्ज करा सकेंगे। लो टेंशन लाइन वाले बिजली कनेक्शन पर ई वाहन साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किए जा सकेंगे। जबकि हाई टेंशन वाले कनेक्शन पर चार रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा।

उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा पेंशन ट्रस्ट अधिभार– बिजली की दरों में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेंशन ट्रस्ट अधिभार ज्यादा चुकाना होगा। दरअसल सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को पेंशन देने का भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। अबतक उपभोक्ताओं को बिजली बिल का पांच फीसद पेंशन अधिभार वसूला जाता था, अब इसे बढ़ाकर सात फीसद कर दिया गया है। इसके साथ ही डिस्काम डीईआरसी के पास बकाया रेगुलेटरी असेट की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से बिजली बिल पर आठ फीसद अधिभार वसूलती रहेगी।

स्थायी शुल्क की दरों में बदलाव नहीं

दो किलोवाट स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 20 रुपये प्रति किलोवाट, दो किलोवाट से ज्यादा और पांच किलोवाट से कम तक 50 रुपये प्रति किलोवाट, पांच किलोवाट से ज्यादा और 15 किलोवाट से कम तक एक सौ रुपये प्रति किलोवाट, 15 किलोवाट से ज्यादा और 25 किलोवाट से कम तक 200 रुपये प्रति किलोवाट और इससे ज्यादा लोड वालों को 250 रुपये प्रति किलोटवाट की दर से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा।

दिल्ली में अस्थायी अस्पतालों के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली । भाजपा ने राजधानी में अस्थायी अस्पताल बनवाने में दिल्ली सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार पर सात स्थानों पर अस्थायी अस्पताल बनवाने में करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में इन नेताओं ने बताया कि इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

आदेश गुप्ता ने कहा कि शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय, जीटीबी अस्पताल परिसर, सरिता विहार और रघुवीर नगर में 1256 करोड़ रुपये की लागत से अस्थायी अस्पताल बनने हैं, लेकिन निविदाओं में भारी घोटाला किया गया। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी की सेवानिवृत्ति के दिन ही सैम इंडिया को निर्माण कार्य सौंप दिया गया।

साथ ही स्ट्रक्चरल ट्यूब के दाम बढ़ने के नाम पर टेंडर में 40 फीसद की वृद्धि कर दी गई। उन्होंने कहा कि द्वारका स्थित 1725 बिस्तरों वाले अस्पताल को अभी तक चालू न करके अस्थायी अस्पताल पर इतनी भारी रकम खर्च की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार घोटालों में लिप्त है,जिसका जवाब उनके पास नहीं है।

मनोज तिवारी ने कहा कि इस परियोजना को मंजूरी बाद में मिली, लेकिन टेंडर पहले ही जारी कर दिया गया। इस मामले में जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को पत्र लिखा है।

संपादकीय

फर्जी खबरों पर कसे शिकंजा

यू-ट्यूब, वेबसाइट समेत सोशल मीडिया पर प्रकाशित-प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों और रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेजा नहीं है। वाकई, ऑनलाइन माध्यमों से अब सत्य से अधिक असत्य सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। इसका एक बा कारण यह है कि तमाम डिजिटल मंच समझ चुके हैं कि सच की तुलना में वे फर्जी खबरों के प्रकाशन-प्रसारण से अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए, वे अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं और ऊल-जुलूल खबरों को सच का चोला पहनाकर परोसने की कोशिश में लगे रहते हैं। शीर्ष अदालत का यह कहना वाजिब है कि फेक न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया पर 'नैरेटिव' गी जाती है। देखा जाए, तो यह एक वैश्विक चुनौती है। इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है और तमाम उपभोगकर्ताओं को छद्म वेश में अपनी गतिविधियां करने की छूट दे दी है। चूंकि लोगों को लगता है कि उनकी पहचान इंटरनेट पर जाहिर नहीं हो सकती, इसलिए वे आभासी दुनिया में ऐसी तमाम हरकतें करते रहते हैं, जो असल जीवन में कतई नहीं कर सकते। फेक न्यूज आज इसलिए भी चलन में हैं, क्योंकि किसी राष्ट्र के कानून उसकी भौगोलिक सीमाओं तक ही लागू होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न कोई मापदंड है, और न कोई नीति। ऐसा कोई समझौता भी नहीं हो सका है, जिसमें तमाम देश अपने-अपने यहां फर्जी खबरों का प्रकाशन-प्रसारण रोकने का सामूहिक प्रयास कर सकें। लिहाजा, स्थानीय स्तर पर इन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। मलयेशिया, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों ने तो अपने-अपने यहां फर्जी खबरों से निपटने के लिए खास कानून बनाए भी हैं। मगर अंतरराष्ट्रीय कानून के न होने से स्थिति संभल नहीं रही। अगर अब भी ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो कुछ समय के बाद इंटरनेट पर यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सी खबर सच्ची है और कौन-सी फर्जी।

रही बात भारत की, तो फर्जी खबरों को रोकने के लिए किसी 'डेडिकेटेड' यानी खास कानून का यहां भी अभाव है। इस मसले पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी ऐक्ट) भी मौन है। हालांकि, 2008 में जब आईटी ऐक्ट में संशोधन किए गए थे, तब उसमें धारा 66-ए जो ी गई थी। इसमें कुछ हद तक फर्जी खबरों से निपटने की व्यवस्था थी। इसमें कहा गया था कि यदि कोई अपने कंप्यूटर अथवा मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित-प्रसारित करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा या पांच लाख तक जुर्माना या फिर दोनों, भुगतना पा सकता है। मगर इस प्रावधान की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और मार्च, 2015 में अदालत ने इसे रद्द कर दिया। जब से धारा 66-ए असांविधानिक घोषित की गई है, फर्जी खबरें परोसने वालों की पौ बारह है। राजनेता, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, बिजनेस समुदाय, कॉरपोरेट आदि सभी इसमें जुटे हैं। लेकिन फर्जी खबरों को रोकने के लिए समर्पित और खास कानून न होने की वजह से आमतौर पर अदालत में दोष साबित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम चाहें, तो कानून-निर्माण में मलयेशिया, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों के अनुभव शामिल कर सकते हैं, जहां इस तरह के कानून काम कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या नेता ऐसा करेंगे?हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे रोकने के कुछ प्रयास किए हैं। 25 फरवरी, 2021 को आईटी रूल्स 2021 प्रकाशित किए गए और उनको अमल में भी लाया गया। इसका एक प्रावधान कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर (सेवा देने वाला) की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने मंच पर बेबुनियाद या झूठी सामग्रियों के प्रकाशन-प्रसारण पर रोक लगाए। सर्विस प्रोवाइडर के शिकायत प्रकोष्ठ को इस बाबत लिखित शिकायत की जा सकती है, जिस पर 15 दिनों में कार्रवाई करने की अनिवार्यता है। मगर मुश्किल यह है कि ऐसे प्रावधान आम लोगों की जानकारी में नहीं हैं। लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं कि वे यह समझ सकें, फर्जी खबर किस तरह उनकी सोच बदल सकती है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि बिना सत्यता जांचे यदि कोई व्यक्ति किसी खबर को (जो झूठी खबर हो) प्रकाशित-प्रसारित करता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आईटी ऐक्ट की धारा 67 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और आरोप साबित होने पर तीन साल तक की सजा या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों सुनाई जा सकती है। जाहिर है, हमें लोगों को जागरूक करना होगा और यह बताना होगा कि फर्जी खबरें उनकी जों को खोखला कर रही हैं। वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और यू-ट्यूब भी इससे संभल सकेंगे। एक अन्य उपाय, इनके खिलाफ कानूनी प्रावधान की व्यवस्था करना भी है। जीवन जीने के अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 के तहत यह किया जा सकता है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सीमा-पार बैठे भारत-विरोधी तत्व फर्जी व झूठी खबरों के प्रकाशन-प्रसारण से हमारी प्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि, एक विरोधाभास भी है। दरअसल, कोई राजनीतिक दल इस दिशा में आगे नहीं बना चाहता, क्योंकि उनके आईटी सेल भी ऐसे ही कामों में शामिल रहते हैं। बहरहाल, फर्जी खबरों की तरह सनीसनीखेज शीर्षकों से प्रकाशित-प्रसारित खबरें भी हमारा खूब नुकसान करती हैं। इस तरह की खबरों में शीर्षक गलत व झूठे होते हैं या फिर उनका मूल खबरों से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत उस सोशल मीडिया मंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कानून की नजर में यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक धोखाधी है, जिसमें कैद और जुर्माने, दोनों का प्रावधान है। मगर अधिकांश लोग ऐसे प्रावधानों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए अगर कुछ ठोस कार्रवाई हो और वह आम लोगों की निगाहों में आए, तब कोई बात बने। इससे फर्जी व झूठी खबरों को परोसने वाली संस्थाओं को भी का संदेश मिलेगा। इसका यह भी मतलब है कि भारतीय दंड संहिता और आईटी ऐक्ट के प्रावधानों की मदद से स्थिति थोडी सुधारी जा सकती है, लेकिन फर्जी खबरों को रोकने के लिए समर्पित और खास कानून न होने की वजह से आमतौर पर अदालत में दोष साबित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम चाहें, तो कानून-निर्माण में मलयेशिया, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों के अनुभव शामिल कर सकते हैं, जहां इस तरह के कानून काम कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या नेता ऐसा करेंगे?

प्रवीण कुमार सिंह

भारत में छह करोड़ से भी अधिक लोगों को ड्रग्स की लत

हम त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो युवा इसके शिकार हो चुके हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ड्रग्स के कारण राह से भटके युवा फिर से सही राह पर आएं और अपने परिवार तथा प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बनें। उन्हें समझाना ही होगा कि वे उचित उपचार और काउंसलिंग के जरिये सही होकर ड्रग्स की लत से मुक्ति पा सकते हैं। इस अभियान की पूर्ण सफलता में हमारे लिए सर्व समाज का सहयोग भी बहुत आवश्यक है।

जब कोरोना वायरस आपके किसी करीबी को संक्रमित करता है, तब आप क्या सोचते हैं? यही न कि वह व्यक्ति जल्द स्वस्थ हो, ताकि संक्रमण और न फैले। वहीं जब कोई व्यक्ति ड्रग्स यानी मादक पदार्थों का सेवन कर रहा होता है, तब आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं! क्यों? ड्रग्स का सेवन भी तो जानलेवा है। यह भी एक महामारी है। ड्रग्स का दानव न केवल जिंदगियां और परिवार तबाह कर रहा है, बल्कि इसका काला कारोबार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अहम स्रोत बना हुआ है। अलगाववादी-आतंकी संगठनों के लिए यह बहुत कमाऊ खेल है। इसी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी बुराई पर नकेल कसने के लिए असम में हम युद्धस्तर पर जुटे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारी सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति और सटीक रणनीति से ड्रग तस्करों पर प्रहार करने में लगी है। इसके उत्साहवर्धक नतीजे भी मिल रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में छह करोड़ से भी अधिक लोगों को ड्रग्स की लत लगी हुई है। इनमें भी अधिकांश किशोर और युवा हैं। यानी देश की युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बनाकर उन्हें अपराध एवं अवसाद की दलदल में धकेला जा रहा है।

इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गत वर्ष 15 अगस्त को 'नशा मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की थी। इसके लिए देश के उन 272 जिलों को चुना गया, जहां सबसे ज्यादा लोग नशे की चपेट में हैं। उनमें नौ जिले असम के भी हैं। दरअसल असम की भौगोलिक स्थिति अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के लिए मुफीद रही है। ड्रग्स तस्करी के लिए दुनिया भर में कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार, लाओस और थाइलैंड के बीच का इलाका) से

नजदीक होने के कारण असम तस्करों के निशाने पर रहता है। वे असम को म्यांमार और शेष भारत के बीच एक कारिडोर के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं। ऐसी सूचना है कि प्रतिबंधित ड्रग्स की खेप मणिपुर और मिजोरम के रास्ते असम लाई जाती है। फिर यहां से दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह पूवरेत्तर में अलगाववादी संगठनों की फंडिंग का भी मुख्य स्रोत है। ड्रग्स तस्करी से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अलगाववाद की आग को भड़काने में खर्च किया जा रहा है।

ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र (यूएनओडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल वैश्विक अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान का योगदान 85 प्रतिशत था। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने देश में ड्रग्स तस्करी बढ़ने की आशंका जताई है। इसका अर्थ है कि देश के पूवरेत्तर और पश्चिमोत्तर दोनों छोर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों और राष्ट्र विरोधी संगठनों के निशाने पर हैं। सुकून देने वाली बात यही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास मोदी जी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के रूप में दृढ़ इच्छाशक्ति वाला निर्णायक नेतृत्व मौजूद है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सवरेपरि है। असम के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद मैंने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में ड्रग्स के अवैध कारोबार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्करों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने और नई पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाकर विकास गतिविधियों में सहभागी बनाने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने असम पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कड़ी कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी है। पुलिस इस आजादी का बखूबी उपयोग कर रही है। उसने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुखर अभियान छेड़ रखा है। वह समन्वित तरीके से ड्रग्स माफियाओं के गिरोहों का सफाया कर रही है। कार्बी-आंगलोंग जिले में पुलिस ने जब बड़ी मात्र में ड्रग्स एवं दवाइयां बरामद कीं तो हमने न सिर्फ पुलिस की हौसला अफजाई की, बल्कि खुद जाकर उसे सार्वजनिक रूप से आग के हवाले किया। नौगांव में बड़ी मात्र में बरामद ड्रग्स पर भी हमने सार्वजनिक तौर पर बुलडोजर चलाया। इनके संदेश स्पष्ट हैं। असम ड्रग्स के अवैध कारोबार के लिए अब मुफीद ठिकाना नहीं रहेगा। इसके साथ ही पूवरेत्तर के अन्य राज्यों से समन्वय भी स्थापित किया गया है। अच्छी बात है कि इसमें सभी राज्यों का सहयोग मिल रहा है।

असम सरकार के संकल्प और मजबूत इरादों से पुलिस के अभियान को बल मिला है। आंकड़ों के आईने में इसे साफ देखा जा सकता है। मैंने इस साल 10 मई को मुख्यमंत्री पद संभाला था, तबसे 5 सितंबर 2021 के बीच प्रदेश में नारकोटिक्स एक्ट (एनडीपीएस) के तहत कुल 1250 मामले दर्ज हुए। इनमें 2162 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 35.5 किलो हेरोइन के अलावा बड़ी मात्र में अन्य नशीले पदार्थ जब्त हुए हैं। इनका अनुमानित बाजार मूल्य 231.31 करोड़ रुपये है। वहीं, इसी एक्ट के तहत 2020 में कुल 980 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1652 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 27.4 किलो हेरोइन के अलावा अन्य नशीले पदार्थ जब्त हुए थे। गोल्डन ट्रायंगल से आने वाली खेप के लिए असम को पारगमन केंद्र यानी ट्रांजिट प्वाइंट बनाने वाले तस्करों के करीब 80 फीसद नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बचे खुचे ड्रग्स माफियाओं को भी अहसास हो जाना चाहिए कि असम में उनकी दाल नहीं गलने वाली। पुलिस उन्हें कभी भी और कहीं भी दबोच सकती है। बेहतर यही होगा कि वे या तो यह काला धंधा छोड़ दें या फिर असम से चले जाएं। हमारा अभियान सिर्फ ड्रग्स का कारोबार खत्म करने तक ही सीमित नहीं है। हम त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो युवा इसके शिकार हो चुके हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ड्रग्स के कारण राह से भटके युवा फिर से सही राह पर आएं और अपने परिवार तथा प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बनें। उन्हें समझाना ही होगा कि वे उचित उपचार और काउंसलिंग के जरिये सही होकर ड्रग्स की लत से मुक्ति पा सकते हैं। इस अभियान की पूर्ण सफलता में हमारे लिए सर्व समाज का सहयोग भी बहुत आवश्यक है।

कैसे बचाओगे लाजज बताओ ना कांग्रेस के युवराज?

पंजाब की सियासत में आए उलटफेर के बाद कपिल सिब्बल को रहा नहीं गया और उन्होंने आलाकमान पर बगावती तंज कर दिया. कपिल सिब्बल ने सवाल उठा दिए कि अभी पार्टी में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है तो आखिर ये फैसले कौन ले रहा है. कहते हैं घर का मालिक हमेशा सही नहीं होता. कभी-कभी उसके गलत फैसले और छोटों को मौका नहीं देने की वजह से ही परिवार टूट की कगार पर पहुंच जाता है. इतना सब होने के बावजूद भी अगर मालिक ना सुधरे तो उस घर का बेड़ा गर्क होना तो तय ही है. आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है. वैसे तो इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन बात अगर पिछले कुछ दशकों की करें तो साल 2004 की कांग्रेस की तस्वीर आज की कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी. 2004 में सोनिया गांधी का प्रचार, देश के गली-मोहल्लों तक पहुंच, बड़े-बड़े भाषण बताते थे कि देश में अब सिर्फ एक ही पार्टी रह गई है और वो है कांग्रेस. लेकिन आज की कांग्रेस तो विलुप्त होने की कगार पर है. राहुल गांधी को फेस बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने कई सूरमा खो दिए. राहुल गांधी को अब भी शायद कन्फ्यूजन है. या तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं के योगदान को समझ नहीं पा रहे या समझना ही नहीं चाह रहे.

2004 से 2014 तक 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस पुरानी जीन्स की तरह बीते हुए कल की तरफ बढ़ रही है. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की चिंता व्यर्थ नहीं है. चिंता इस बात की कि वो कांग्रेस जिसका झंडा बच्चे-बच्चे के हाथ में हुआ करता था. सिर्फ पंजा ही पंजा दिखता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजे पर से लोगों का भरोसा ही उठ गया. इसका मतलब यही है कि पार्टी में बड़े नेताओं की सुनी नहीं जा रही. अभी भी आलाकमान को ये अकल नहीं आई कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चलती है ना कि किसी एक से.

पंजाब की सियासत में आए उलटफेर के बाद कपिल सिब्बल को रहा नहीं गया और उन्होंने आलाकमान पर बगावती तंज कर दिया. कपिल सिब्बल ने सवाल उठा दिए कि अभी पार्टी में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है तो आखिर ये फैसले कौन ले रहा है. आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बड़े-बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. कपिल सिब्बल की चिंता भी जायज है, इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी करीब-करीब इसी राह में हैं. पार्टी छोड़कर जाने वालों की लिस्ट तो लंबी है लेकिन बड़े चेहरों का जाना पार्टी के क्रियाकलापों पर प्रश्न जरूर खड़े कर रहा है, कि क्या वाकई आलाकमान पार्टी के बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं देती है? क्या कांग्रेस की परिभाषा परिवारवाद से ही जानी जाती है?

कांग्रेस के धुरंधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और दिल्ली में अमित शाह से मिलना इस बात का संकेत है कि पार्टी किसी ईमानदार नेता और कार्यकर्ता के साथ नहीं चलेगी बल्कि अपने हिसाब और अपने फायदों को देखकर ही चलेगी. बात अगर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल नवजोत सिंह सिद्धू की करें तो कांग्रेस को उनपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं है. पार्टी ने सिद्धू को भले ही पंजाब का अध्यक्ष बना दिया हो लेकिन उनके तौर तरीकों से साफ लगता है कि सिद्धू पर पार्टी लगाम कसना चाह रही है. ऐसे में ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है.

2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस विपक्ष में है. कांग्रेस का विपक्ष में रहना तो समझ में आता है लेकिन इनकी रणनीति यही बता रही है कि इनके गलत फैसले पार्टी को डुबो रहे हैं. विपक्ष में रहकर भी कांग्रेस कोई मुद्दे नहीं खड़े कर पा रही है, जबकि बीजेपी ने 2014 और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव मुद्दों को आधार बनाकर ही जीता था. 2017 का यूपी चुनाव हो या 2020 का बिहार चुनाव. मध्यप्रदेश हो या कर्नाटक, पार्टी आलाकमान ने कभी एक राजनीतिक रणनीति पर काम नहीं किया. 10 जनपथ से होने वाले फैसलों का नतीजा ही है कि कांग्रेस पहले देश और धीरे-धीरे ज्यादातर प्रदेशों से क्लीन बोल्ड हो चुकी है. कांग्रेस के तौर तरीकों से तो यही लगता है कि 2022 और 2024 जैसे चुनाव पर इनका फोकस ही नहीं है. लाल निशान छोड़ कन्हैया कुमार कांग्रेसी जरूर बन गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के खेवनहार साबित भी होंगे इस पर शंका है. क्योंकि कोई भी नेता अपने इलाके और समाज के हिसाब से ही अपने वोटों का फायदा देखते हुए कुछ करना चाहता है. कन्हैया कुमार जैसे नेता जिन पर देशद्रोही नारों के आरोप लग चुके हैं, उनपर 10 जनपथ का रवैया ही ये तय करेगा कि वह पार्टी के लिए कितने बड़े खेवनहार साबित होंगे और उसे कहां तक ले जाएंगे. अभी तक के हालात से तो साफ है कि पार्टी के फैसलों ने बड़े-बड़े नेताओं को खो दिया है. ऐसे में आलाकमान एजेंडा क्या सेट करेगा. हाल तो अभी यही है कि वो तो अंतर्कलह मिटाने में भी नाकाम साबित हुआ है.

चीन को चुनौती

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो भाषण दिया, वह ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें अफगानिस्तान, आतंकवाद और कोरोना जैसी चुनौतियों पर बड़ी स्पष्टता और उतनी ही गंभीरता से भारत का पक्ष रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की अहमियत इस बात में है कि छोटे मसलों में उलझने के बजाय इसमें बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों से उभरी चुनौतियों को रेखांकित करने की कोशिश की गई और इससे भी बड़ी बात यह कि इन चुनौतियों के पीछे छिपे अवसर को पहचानते हुए उसका उपयुक्त इस्तेमाल करने की दूरदर्शिता दिखाई गई है।

यह अकारण नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में चित्रित करते हुए वैश्विक बिरादरी को याद दिलाया कि हमारे देश में लोकतंत्र की हजारों वर्षों की परंपरा है।

विविधता हमारे समाज की पारंपरिक विशिष्टता रही है। कामकाज में पारदर्शिता हमारी स्वाभाविक शैली है। गौर करने की बात यह है कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, जहां चीन मुकाबले में कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता। न तो वहां लोकतंत्र है और ना ही पारदर्शिता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ठीक ही कोरोना की उत्पत्ति और वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के कैंसिलेशन का मुद्दा उठाया।

वैश्विक बिरादरी इन दोनों सवालों पर चीनी रुख में पारदर्शिता की कमी से जूझ रही है। दुनिया देख सकती है कि एक तरफ भारत है, जो कोरोना की चुनौती से खुद जूझते हुए भी दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ चीन है जो कोरोना की उत्पत्ति की गुत्थी को सुलझाने तक में सहयोग देने को तैयार नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए बड़ी खूबसूरती से वैश्विक मामलों पर बोलने के चीन के नैतिक अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया। ध्यान रहे, नए अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के लिहाज से चीन का वर्चस्ववादी और आक्रामक रुख ही सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री का यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि चीन का रुख न केवल अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों के लिए खतरा बनता जा रहा है बल्कि यह आधुनिकता और प्रगतिशील मूल्यों के भी खिलाफ है।

ऐसे में चीन के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाने की कोई भी कोशिश उदार वैश्विक मूल्यों को खतरे में डालेगी। इसी बिंदु पर भारत के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुलते हैं।

निवेश के अवसरों से भरपूर एक लोकतांत्रिक और पारदर्शितापूर्ण समाज के तौर पर भारत बेहतर विकल्प के रूप में दुनिया के सामने मौजूद है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह लेने को भारत तैयार है। भारत और वैश्विक समुदाय का यह साथ न केवल भारत के विकास की दृष्टि से बल्कि सद्भावपूर्ण, लोकतांत्रिक और उदार दुनिया सुनिश्चित करने के लिहाज से भी उपयोगी होगा।

संकीर्ण सोच और असंवैधानिक आचरण छोड़ राजधर्म का पालन करें उद्धव ठाकरे

संविधान में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर विभेद का पूर्ण निषेध है। ऐसे में क्षेत्र विशेष के लोगों को अपराधी मानकर पुलिस-प्रशासन को निर्देशित करना संकीर्ण सोच और अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक आचरण की अभिव्यक्ति है। इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर भी आघात होता है। ऐसे में शिवसेना और उद्धव ठाकरे को यह समझने की जरूरत है कि सभी नागरिकों के अधिकारों और सम्मान का संरक्षण करके ही संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया जा सकता है। यही राजधर्म भी है।

बीते दिनों मुंबई में एक महिला दुष्कर्म की शिकार हुई और उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस वीभत्स अपराध की दिल्ली के निर्भया कांड से भी तुलना की गई। चूंकि इस अपराध के आरोपित की जड़ें उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जुड़ी थीं, तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ प्रलाप का अवसर मिल गया। पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत ने इस अपराध को 'जौनपुर पैटर्न' करार दिया। इतना ही नहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी आड़ में पुलिस को दूसरे प्रांत के लोगों को चिन्हित करने और उनकी निगरानी का निर्देश देकर संकीर्ण राजनीति का परिचय दिया।

राउत जैसे नेता तो आए दिन अपने उलजुलूल बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, मगर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर पर बैठे ठाकरे की बयानबाजी बड़ी विडंबना है। क्या वह मुंबई के आपराधिक अतीत एवं वर्तमान और कुख्यात अंडरवर्ल्ड को भूल गए जो मायानगरी में हो रहे अपराधों का ठीकरा दूसरे प्रांतों के लोगों पर फोड़ रहे हैं। क्या वह भूल गए कि मुंबई नगर को चमकाने में बाहरी लोगों ने कितना परिश्रम किया है। जो भी हो, शिवसेना का यह रवैया कोई नया नहीं है, लेकिन हैरानी तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा जैसे दलों के इस मामले पर मौन को लेकर होती है जो गठबंधन सरकार में शिवसेना की साझीदार हैं। भाजपा ने जरूर इस मुद्दे पर प्रतिकार किया है।

राउत ने अपराधों का सामान्यीकरण करते हुए जिस 'जौनपुर पैटर्न' का जिक्र किया है, उसे

समझने से पहले हमारे लिए राजनीति के 'शिवसेना पैटर्न' को समझना होगा। शिवसेना संकीर्ण अस्मितावादी और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाले सबसे पुराने दलों में से एक है। उपरोक्त आपराधिक घटना को स्थानीय बनाम बाहरी और मराठी बनाम प्रवासी का रंग जानबूझकर दिया जा रहा है। इसके मूल में वोट बैंक की राजनीति है। कुछ ही समय बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने हैं। उसके मद्देनजर शिवसेना मराठा वोटों को लामबंद करने की फिराक में है। बीएमसी के पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। उसमें शिवसेना बहुत मामूली अंतर से बाजी मार गई। असल में बीएमसी मात्र एक स्थानीय निकाय न होकर देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है। उसका सालाना बजट कई राज्यों की सरकारों से भी अधिक है। बीएमसी शिवसेना की सियासी ताकत का मूल आधार रही है। शिवसेना इस आधार को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती। भाजपा ने भी इस चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में बड़ी तादाद में कोंकणी लोग रहते हैं। इसीलिए उन्हें साधने के लिए कोंकण के क्षत्रप नारायण राणो को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इससे शिवसेना की पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। इसके संकेत बीते दिनों राणो के साथ टकराव के रूप में प्रत्यक्ष भी दिखे।

बीएमसी के चुनाव में उत्तर भारतीयों की अहम भूमिका होने के बावजूद शिवसेना उन्हें निशाना बनाने से बाज नहीं आती। इसी कड़ी में शिवसेना ने पिछले कुछ समय से उत्तर भारतीयों विशेषकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपनी नफरत का शिकार बनाया है। वैसे भी यही माना जाता है कि उत्तर भारतीयों का भाजपा के प्रति झुकाव रहता है। यह पहलू शिवसेना को और कुपित करता है। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुंबई में गुजरातियों और दक्षिण भारतीयों की अच्छी-खासी तादाद होने के बावजूद शिवसेना उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाती। गौर करने वाली बात है कि पिछली सदी के सातवें दशक में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बिगुल बजाकर ही अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई थी।

इसमें कोई दोराय नहीं कि शिवसेना का जन्म और विकास क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और संकीर्ण अस्मितावादी राजनीति का प्रतिफलन है। भाजपा से गठबंधन के दौरान जरूर उसके ऐसे तेवर कुछ नरम पड़े थे, लेकिन अब वह फिर पुराने दर्ढे पर लौटती दिख रही है। उसे कम से कम अपने ही परिवार के राज ठाकरे से कोई सबक सीखना चाहिए, जिन्होंने गाजे-बाजे के साथ मनसे के रूप में मराठा अस्मिता के नाम पर अपनी आक्रामक राजनीति शुरू की थी, लेकिन वह अब राजनीतिक विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं और अब नए प्रयोग करने पर विवश हैं। शिवसेना को इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि मराठा कार्ड अब वोट दिलाने और चुनाव जिताने वाला नहीं रह गया है। एक समय अवश्य ऐसी राजनीति के लिए उर्वर था, किंतु वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बाद स्थिति परिवर्तित हो गई है। आज 'मराठा माणूस' भी वैश्वीकरण और प्रवासन का लाभार्थी है। इसलिए संभव है वह क्षेत्रीय भावना से बचते हुए भेड़चाल में वोट न करे। महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे प्रांतों के लोगों की निगरानी के जो निर्देश दिए हैं, उससे लोगों के उत्पीड़न की आशंका बढ़ गई है। साथ ही पुलिस-प्रशासन पर भी काम का अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। उसकी कार्यकुशलता प्रभावित होगी। इससे भ्रष्टाचार के लिए भी द्वार खुलेगा। यह कदम संविधान विरोधी भी है। संविधान में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर विभेद का पूर्ण निषेध है। ऐसे में क्षेत्र विशेष के लोगों को अपराधी मानकर पुलिस-प्रशासन को निर्देशित करना संकीर्ण सोच और अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक आचरण की अभिव्यक्ति है। इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर भी आघात होता है। ऐसे में शिवसेना और उद्धव ठाकरे को यह समझने की जरूरत है कि सभी नागरिकों के अधिकारों और सम्मान का संरक्षण करके ही संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया जा सकता है। यही राजधर्म भी है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

सीएम योगी का विपक्षियों पर तंज, कहा- सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली...। उन्होंने कहा कि जनता इन लोगों के घड़ियाली आंसू से सावधान रहे। यह वही लोग हैं जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करके सत्ता तक पहुंचाया। इन्हीं अपराधियों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ। यह लोग प्रदेश को बदनाम करने और अराजकता फैलाने में कोई अवसर गंवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले गोरखपुर में दुखद घटना घटित हुई और उसी दिन मैंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने कहा था। मामले में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की अपराध और आपराधियों की जीरो टोलरेंस की नीति है, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। मैंने कानपुर प्रशासन को पहले ही बोल दिया था कि मुझे पीड़ति परिवार से मुलाकात करनी है । सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और उनके परिवार से मुलाक़ात की। कहा कि किसी भी दोषी को छोडेंगें नहीं, हम जाँच करवा रहे हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। दुखद घटना है जो भी दोषी है बख्शा नहीं जायेगा।

कानुपर के डीएवी कालेज फूलबाग मैदान में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कानपुर के 5.55 अरब रुपये के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद पांच बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्रासन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान राशि की प्रतीकात्मक चेक दी। मंच पर भारत माता की जय और वंदेमातरम का उद्घघोष के साथ संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने सबसे पहले मंचासीन सांसद, विधायक एवं संगठन से जुड़े सभी भाजपा नेताओं और पंडाल में मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के प्रथम औद्योगिक नगर, जिसने मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अपना नाता जोड़ा था। कानपुर नगर की साढ़े पांच सौ करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज ये मंच आपके सबके बीच में लेकर आया है। कानपुर एक बार फिर से अपनी नई आभा के साथ देश के अंदर स्थापित हो रहा है। ये कानपुर कभी यूपी और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था। लेकिन, आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस माडल न होने और यहां के नागरिकों के लिए शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण उद्योग बंद होते गए। न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा को खराब करने के लिए अगर किसी नगर को दोषी ठहराया जाता था तो वह कानपुर हुआ करता था।

लेकिन, आज हम प्रधानमंत्री जी के अभारी हैं, उनके नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसमऊ नाला जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मइया में उड़ेलता था। आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, अब एक भी बूंद नाले के माध्मय से मां गंगा में नहीं जाती है। मां गंगा की निर्मलता और अविरलता के साथ अब कानपुर के सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर को केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर कई योजनाएं दी हैं। चाहे वह कानपुर मेट्रो का चल रहा तेजी के साथ कार्य हो रहा है, अबतो यहां मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है। नवंबर के अंत में यहां मेट्रो का संचालन भी प्राप्त करने

वाले है, यह कानपुर का उभरता हुआ नक्शा है। यह वही कानपुर है, जहां पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, बेमानी और भ्रष्टाचार के कारण यहां पर उदासीनता छा गई थी। लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, एक साथ तीन विमान उतरकर पार्क हो सकते हैं और पांच सौ लोग एक साथ टर्मिनल में आकर विकास को देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये बदलता हुआ कानपुर है और इसी क्रम में तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है।

मेट्रो, डिफेंस कारीडोर, एयरपोर्ट निर्माण आदि तब संभव हुए हैं, जब मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं और अपना एक एक पल विकास के लिए और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए समर्पित करते हैं। तभी कानपुर के किसी वार्ड, गली और मोहल्ले में विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस सबके लिए मंच पर उपस्थिति जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करने और कानपुर वासियों को बधाई देते मैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। सभी परियोजनाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि अन्नप्रासन के समय आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने निडर होकर यहां पर मेरे सामने हंस रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बच्चे बयां कर रहे थे, जिसमें उन्हें यूपी में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रदेश का हर बच्चा गौरव की अनुभूति कर सकता है कि वह देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब यूपी में भाजपा की सरकार आ गई थी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का ये संकट उन लोगों ने खड़ा किया, जिन्होंने पेशेवर अपराधियों और माफिया के पास प्रदेश की स्थिति और विकास को गिरवी रख दिया था। देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकृत प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। जिस प्रदेश में प्रभु श्रीराम और श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था, बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को स्थापित करने का सौभाग्य है, मां गंगा गंगोत्री से सबसे अधिक दूरी करती है, उस उत्तर प्रदेश के लिए नौजवान के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यह वही लोग हैं, जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों को राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता में काबिज होने और विकास की परियोजनाओं पर जबरन कब्जा और डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। आज मैं देख रहा था कि मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में था, मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था कि दो दिन पहले गोरखपुर में दुखद घटना हुई थी। मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिये, और दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, मैंने सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ति परिवार से मैं मिलना चाहूंगा। क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। इस घटना के लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, सभी की जवाबदेही भी तय करेंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, यह किसी से छिपा नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पेशेवर अपराधियों के सामने गिरवीं रखा था, उनके सामने एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने...।

उन्होंने कहा कि ये लोग कोई अवसर नहीं गंवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, अराजकता पैदा करने, केवल अपराधियों और माफिया की पैरवी करने और प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं पर कहीं न कहीं ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं लोगों को मिल रही हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। आज इनको परेशानी कब होती है, जब किसी गरीब को शौचालय या आवास मिल जाता है। किसी वृद्धावस्था पेंशन, निरश्रित महिला को पेंशन और दिव्यांगजन को पेंशन मिलती है, किसान को सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है तो इन लोगों को बुरा लगता है। किसी पेशेवर अपराधी की अवैध संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलता है तो इनको बुरा लगता है। इनकी सहानुभूति प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, न पहले थी और आगे कभी आने वाली है। ये लोग तो वो हैं, जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। नौकरी निकलती थी और उसपर कैसे डकैती पड़ती थी, एक परिवार वसूली पर निकल पड़ता था। आज हमारी सरकार ने साढ़े चार साल पूरे किए है, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में साढ़े चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। इस सरकारी नौकरी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। इसमें किसी जाति, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं देखी गई, प्रदेश का नौजवान योग्य होगा और वह परीक्षा पास करेगा तो सरकार उसे सेवा का अवसर देगी और वह प्रदेश के विकास में योगदान करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, श्रम विभाग की कन्या विवाह सहायता योजना समेत सात योजनाओं के 16,400 लाभार्थियों को बुलाया गया है। पीएम आवास योजना शहरी के आवंटी राघवेंद्र, निसार बानो, उजमा रिजवी समेत पांच लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से वेंडर सत्य नारायण, सीमा ड्क्षसह समेत पांच को वित्तीय मदद की चेक मिलेगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हरपाल सिंह, अर्जुन सिंह, बचान समेत पांच किसानों को प्रमाण पत्र मिलेगा। दर्श, विधि, रिद्धि, वंशिका और अनुराग का अन्नप्राशन मुख्यमंत्री खुद करेंगे।

संक्षिप्त खबर

अब 15 हजार नहीं, नई पाइपलाइन से एक लाख 30 हजार लोगों को मिलेगा मुफ्त पानी कनेक्शन

धनबाद । नगर निगम क्षेत्र में दो लाख 22 हजार हाउसहोल्ड हैं। इनमें महज 34 हजार ने ही पानी कनेक्शन ले रखा है। नई जल संयोजन नियमावली 2020 के तहत नई पाइपलाइन के जरिए लगभग एक लाख 30 हजार लोगों को निश्शुल्क पानी कनेक्शन मिलेगा। प्रथम चरण में 15 हजार को निश्शुल्क पानी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 15 हजार को ही निश्शुल्क पानी कनेक्शन देने की बात की जा रही थी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अब नई पाइपलाइन के जरिए सभी को निश्शुल्क पानी कनेक्शन मिलेगा। कामर्शियल पानी कनेक्शन के लिए शुल्क देना होगा। पुरानी पाइपलाइन में यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी तक 680 निश्शुल्क पानी कनेक्शन दिया जा चुका है। धनबाद में इस समय तीन जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं। वार्ड एक से 13 तक 166 करोड़ की अम्रुत योजना श्रीराम ईपीसी एजेंसी कर रही है। वार्ड 34 से 52 तक 310 करोड़ की जलापूर्ति योजना का काम जेएमसी एजेंसी के जिम्मे है। इसी तरह 589 करोड़ की मैथन से धनबाद तक समानांतर पाइपलाइन, धनबाद-सिंदरी में संप बनाने और वार्ड 14 से 33 तक मिसिंग पाइपलाइन का काम एलएंडटी एजेंसी कर रही है। वार्ड 53, 54 और 55 में भी एलएंडटी को काम करना है।

पानी कनेक्शन की प्रक्रिया- कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और होल्डिग नंबर देना होगा। निश्शुल्क पानी कनेक्शन पाने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त कोई कनेक्शन लेता है तो उसके लिए शुल्क निर्धारित है। वाटर मीटर में जितना लीटर दिखेगा, उतना ही बिल भुगतान करना होगा। वाटर कनेक्शन को निकाय के प्रापर्टी टैक्स पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी का मासिक यूजर चार्ज का बिल पोर्टल पर आनलाइन अपडेट होता रहे। इस व्यवस्था के लागू होने से नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

वाहनों का तीन सौ करोड़ रुपये टैक्स बकाया, वसूलने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

रायपुर । प्रदेश की सड़कों पर बिना टैक्स पटाये वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों का करीब तीन सौ करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया है। वाहन संचालकों से परिवहन विभाग टैक्स वसूलने में फेल साबित हो रहा है। अब परिवहन विभाग वन टाइम सेटलमेंट नामक स्कीम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों से परिवहन विभाग द्वारा जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। वाहन स्वामी को वाहन का टैक्स और ब्याज की राशि अदा करनी पड़ेगी। वन टाइम सेटलमेंट योजना के बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनकी सूची बनाकर विभागीय कार्यालय में चस्पा करने के साथ विभाग की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। साथ ही उनके वाहन का पंजीयन रद कर दिया जाएगा। राशि वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मुख्यालय में मंगलवार को प्रदेश भर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन अपर आयुक्त दीपांशु काबरा ने यह निर्णय लिया है। इससे वाहन स्वामियों को काफी लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि प्रदेशभर में पांच लाख से अधिक संख्या में व्यावसायिक वाहन दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग एक साल में 25 अरब से अधिक का टैक्स वसूलता है। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेशभर के वाहन संचालकों द्वारा कई सालों से टैक्स की राशि जमा नहीं की जा रही है। इस कारण प्रदेशभर में करीब तीन सौ करोड़ बकाया हो गया है। वाहन स्वामियों को लाभ देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू कर रहा है। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस स्कीम के अंतर्गत एक अप्रैल 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के वाहनों से जुर्माना राशि नहीं ली जाएगी। उसके बाद भी यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर प्रदेशभर में चलने वाली गाड़ियों तथा उनके स्वामियों के नाम, चालान की डिटेल दर्ज है। वेबसाइट खोलकर वाहन क्रमांक डालने पर वाहन से संबंधित सारी जानकारी सामने आ जाती है। इसमें आनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है।

कांग्रेस ने कुशेश्वरस्थान से प्रत्याशी चयन को बनाई पांच सदस्यीय कमेटी, दो अक्टूबर तक सौंपनी होगी सूची

पटना। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वरस्थान से पार्टी प्रत्याशी के चयन के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी से चयनित उम्मीदवार के नामों की सूची दो अक्टूबर तक मांगी गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने इस विधानसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने और उम्मीदवारों के चयन के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें आनंद माधव, कपिल देव प्रसाद यादव, कैसर खान, आइपी गुप्ता और अजय पासवान को शामिल किया है।पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कमेटी को अगले दो दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपनी होगी। इस सीट को लेकर कांग्रेस और उसकी सहयोगी राजद में खींचतान जारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि यह सीट 2020 चुनाव में उसके पास थी लिहाजा उपचुनाव में भी इस सीट पर पहला अधिकार उसका बनता है। तारापुर और कुशेश्वरस्थान सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से इन दोनों सीटों पर दावेदारी पहले ही ठोक दी गई है। वहीं बुधवार को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी इशारों में कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पिछली विधानसभा चुनाव के में इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चनाव मैदान में थे।

अब 15 हजार नहीं, नई पाइपलाइन से एक लाख 30 हजार लोगों को मिलेगा मुफ्त पानी कनेक्शन

धनबाद । नगर निगम क्षेत्र में दो लाख 22 हजार हाउसहोल्ड हैं। इनमें महज 34 हजार ने ही पानी कनेक्शन ले रखा है। नई जल संयोजन नियमावली 2020 के तहत नई पाइपलाइन के जरिए लगभग एक लाख 30 हजार लोगों को निश्शुल्क पानी कनेक्शन मिलेगा। प्रथम चरण में 15 हजार को निश्शुल्क पानी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 15 हजार को ही निश्शुल्क पानी कनेक्शन देने की बात की जा रही थी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अब नई पाइपलाइन के जरिए सभी को निश्शुल्क पानी कनेक्शन मिलेगा।

कामर्शियल पानी कनेक्शन के लिए शुल्क देना होगा। पुरानी पाइपलाइन में यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी तक 680 निश्शुल्क पानी कनेक्शन दिया जा चुका है। धनबाद में इस समय तीन जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं। वार्ड एक से 13 तक 166 करोड़ की अम्रुत योजना श्रीराम ईपीसी एजेंसी कर रही है। वार्ड 34 से 52 तक 310 करोड़ की जलापूर्ति योजना का काम जेएमसी एजेंसी के जिम्मे है। इसी तरह 589 करोड़ की मैथन से धनबाद तक समानांतर पाइपलाइन, धनबाद-सिंदरी में संप बनाने और वार्ड 14 से 33 तक मिसिंग पाइपलाइन का काम एलएंडटी एजेंसी कर रही है। वार्ड 53, 54 और 55 में भी एलएंडटी को काम करना है।

पानी कनेक्शन की प्रक्रिया- कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और होल्डिग नंबर देना होगा। निश्शुल्क पानी कनेक्शन पाने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त कोई कनेक्शन लेता है तो उसके लिए शुल्क निर्धारित है। वाटर मीटर में जितना लीटर दिखेगा, उतना ही बिल भुगतान करना होगा। वाटर कनेक्शन को निकाय के प्रापर्टी टैक्स पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी का मासिक यूजर चार्ज का बिल पोर्टल पर आनलाइन अपडेट होता रहे। इस व्यवस्था के लागू होने से नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर के मनीष गुप्ता के परिवार से मिलते हुए, जिनकी कथित तौर पर गोरखपुर में पुलिस ने हत्या कर दी थी।

आगरा में युवती से दोस्ती कर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

आगरा । एत्माद्दौला इलाके में मुस्लिम युवक ने तीन साल पहले युवती से दोस्ती की। युवती का आरोप है कि युवक ने इस दौरान उसका शारीरिक शोषण किया। उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दी। यही नहीं, कुछ लोगों को घर भेजकर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने युवक समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

एत्माद्दौला इलाके की रहने वाली महिला के अनुसार तीन साल पहले सलमान नामक युवक से उसकी मुलाकात हुई। आरोपित ने प्यार का नाटक करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसका शारीरिक शोषण करने लगा।

इस दौरान उसका एक वीडियो भी बना लिया। उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके शोषण कर रहा था। विरोध करने पर उसकी वीडियो को इंटरनेट मीडिया में डालने की धमकी दी। बदनामी के डर से वह चुप रही। इस दौरान आरोपित सलमान ने उसका गर्भपात भी करा दिया। महिला का आरोप है कि 12 सितंबर को सलमान ने शाकिर, शाहरूख, गोलू, एजाज, भूरा आदि को उसके घर भेजा। महिला का आरोप है उक्त सभी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

विरोध करने पर जातिसूचक शब्द कहे। उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दी। उसने पति को पूरे मामले की जानकारी दी। पति के साथ थाने पहुंचकर महिला ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर एत्माद्दौला देवेंद्र शंकर पांडेय ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में अपराधी छवि वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का निर्देश, शीघ्र होगी जांच

लखनऊ । गोरखपुर में एक प्रापर्टी डीलर की हत्या के मामले में तीन पुलिसकर्मियों के नामजद होने के बाद से अपराधी छवि वाले प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में गृह विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अपराधी छवि वाले प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस जांच में सभी दोषी मिलने पर सभी को तत्काल बर्खास्तगी का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश के सभी दागी पुलिसर्ज़्मियों की जांच करवाने और सूची बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गृह विभाग की जांच में दोषी मिलने सभी अपराधी छवि वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान तथा एडीजी ला एंड आर्डर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में दो कमेटियां बनाकर प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों का रिकार्ड रिव्यू करेंगी। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने या फिर किसी मामले में दोषी पाए जाने पर इनको जबरिया रिटायर और बर्खास्त कर दिया जाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं। यह तो कतई स्वीकार्य नहीं है। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराएं। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। इसके साथ ही अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों की बर्खास्तगी की जाए।

अखिलेश के बाद शिवपाल यादव भी पहुंचे कानपुर, मनीष के स्वजन से मिलने प्रियंका भी आ सकती हैं कानपुर

लखनऊ। पुलिस की रेड के दौरान गोरखपुर में कानपुर के प्रापर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के बाद अब मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कानपुर पहुंचने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क मार्ग से कानपुर जाकर मनीष गुप्ता के पिता तथा पत्नी मीनाक्षी से भेंट की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी कानपुर पहुंचे हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी शाम तक लखनऊ से कानपुर जाने का कार्यक्रम है।प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गोरखपुर में कानपुर के प्रापर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या पर आश्चर्य जताने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया। शिवपाल सिंह यादव के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी लखनऊ दौरे के बीच में ही शाम तक कानपुर जाकर मनीष गुप्ता के स्वजन से मिलने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी गुरुवार शाम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में बैठक के बाद शाम को चार बजे के बाद कानपुर दौरे पर जा सकती हैं।

वारिसलीगंज में अधिकारियों की लापरवाही से करोडो की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन के दीवारों पर गंदी एवं अश्लील गालियां

वारिसलीगंज (नवादा)। वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था को गांधी के परिकल्पना की व्यवस्था कही जाती है। जिसके तहत हर ग्राम पंचायत के लोगो के लिए एक ही छत के नीचे हर प्रकार की सरकारी सुविधा मुहैया करवाई जा सके। जिसके लिए पंचायत के लोगों को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का कार्यालय एवं बाबुओं की कुर्सियों के इर्द गिर्द घूमना पता है। इस समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मुक्ति दिलाने को ले सरकार ने गांधी जी के सपनो को अमलीजामा पहनाने के तहत पंचायतीराज विभाग के द्वारा हर पंचायत मुख्यालय में करोो रूपये खर्च कर पंचायत सरकार भवन बनवाना था। जिसको अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाओं से लैस कर पंचायत स्तर के अभी कर्मचारियों का सुसज्जित कार्यालय चालू करवाना था। परंतु अब तक वारिसलीगंज प्रखंड के 16 पंचायतो में से दो पंचायत चकवाय एवं हाजीपुर में पांच वर्ष पूर्व पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि मकनपुर एवं ठेरा पंचायत में भवन निर्माणाधीन है।

आज पांच वर्ष पूर्व उद्घाटन हुए हाजीपुर पंचायत सरकार भवन की स्थिति से आपको अवगत करवा रहा है, दैनिक जागरण। गांव से उत्तर पशिचम पौरा नहर से 100 मीटर की दूरी पर 2013 में भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई। जो 2015 में बनकर तैयार हो गया। जबकि हा?ीपुर के पंचायत सरकार भवन 2017 में शुभारंभ किया गया है। परंतु अधिकारियों की उदासीनता की वजह से भवन शौचालय से भी बदतर स्थिति में तब्दील हो चुका है। गंदगी इतनी की कमरे से दुर्गन्ध आती है। ग्रामीण बताते हैं कि उदघाटन के बाद कोई भी नियुक्त कर्मचारी भवन में आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अतः असामाजिक तत्वों द्वारा खिडकी एवं दरवाजे का किबा? समेत अन्य सामग्रियों को या तो गायब कर दिया गया है या फिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। भवन के निचली तल में यत्र तत्र शौच किया मिलता है। जबकि ऊपरी तल में जगह जगह गांजा का नशा करने वालों द्वारा आग जलाकर गुल तैयारी का अबशेष पाया जाता है। भवन के बाहर परिसर में बना एक कमरा जिस पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम एवं आरटीपीएस संबंधित जानकारी अंकित है उसमें ताला बंद पाया गया। ग्रामीण पूर्व मुखिया सह हाजीपुर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष वयोवृद्ध सुंदर कुशवाहा कहते हैं कि किसी किसी सप्ताह में पंचायत में नियुक्त डाटा ऑपरेटर आकर एकाध घंटे बैठकर चले जाते हैं। स्थानीय बीडीओ को पंचायत सरकार भवन के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतः करो की लागत से बना भवन उपयोगिता हीन होकर गंजेडियो का अड्डा बन गया है। पंचायत सरकार भवन के शुभारंभ होने के बाद पंचायत क्षेत्र के संबधित ग्रामीणों को राजस्व रसीद, दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आय, आवासीय, जन्म-मृत्यु प्रमाण, शादी विवाह निबंधन प्रमाण पत्रों को बनाने के अलावे,

राष्ट्रीय जैविक दबाव (स्ट्रेस) प्रबंधन संस्थान खुलने से बेहतर कृषि की उम्मीद

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में मंगलवार को राष्ट्रीय जैविक दबाव (स्ट्रेस) प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करते हुए राज्य में कृषि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की संभावनाओं का द्वार खोला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) से संबद्ध यह संस्थान मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान के साथ-साथ किसानों के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। शोधार्थी भविष्य की खेती की दिशा तय करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य के लिए यह उपहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां की 70 फीसद से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इस संसाधन में फसलों के स्वास्थ्य के जैविक अनुसंधान के साथ-साथ प्रबंधन पर भी अनुसंधान होना है। यहां के विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान तो देंगे ही, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे, जो उनकी आय में वृद्धि का आधार बनेगा। प्रदेश सरकार पहले ही मौसम के अनुरूप फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटी है तथा मिशन मिलेट के जरिए ज्वार-बाजरे की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए गोबर से जैविक खाद और बिजली उत्पादन के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। साथ ही फसलों के मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया है। रायपुर का राष्ट्रीय जैविक दबाव प्रबंधन संस्थान का इसी मामले में अहम योगदान होगा। जलवायु सहिष्णु तकनीकी और पद्धतियों के विकास एवं जमीनी स्तर तक इसके प्रचार-प्रसार के साथ भागीदारी और जागरूकता पर केंद्र और राज्य सरकार का जोर है। इन बातों के साथ यह भी जरूरी है कि वर्ष 2012 से संचालित इस संस्थान में तय संख्या में विज्ञानियों की यथाशीघ्र नियुक्ति हो। वर्तमान में यहां एक चौथाई विज्ञानियों से ही काम चलाया जा रहा है। शोध अनुसंधान में उनकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी भी नहीं हैं। इस संबंध में संस्थान की तरफ से पहले भी आइसीएआर से निवेदन किया जाता रहा है। अगर जीवंतता न हो तो आकर्षक भवनों की स्थिति समय काल के साथ खंडहर जैसी हो जाती है। जिम्मेदार लोगों को समझना होगा कि विज्ञानियों और विद्यार्थियों के बिना सिर्फ भवन के दम पर कोई संस्थान गौरव नहीं हासिल कर सकता।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने स्व. माधवराव सिंधिया को किया नमन

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया की पुण्य तिथि पर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास सभाकक्ष में स्व. माधवराव सिंधिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और मध्यप्रदेश के हित में उनके द्वारा दिए गए योगदान का स्मरण किया। कुरवाई विधायक हरि सप्रे भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि मध्यप्रदेश की माटी के रत्न पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। अपने कार्यों और पुनीत विचारों के माध्यम से आप सदैव प्रदेश वासियों के हृदय में रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर 2001 को एक विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था।

कमलनाथ ने सिंधिया की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व.माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। विभिन्न दायित्वों पर रहकर जनहित में किए गए उनके कार्य सदैव अविस्मरणीय हैं।

आम आदमी की थाली को पौष्टिक बनाएगा हरा सोयाबीन

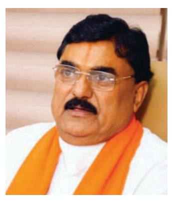

भोपाल । कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि दलहन और तिलहन के रूप में इस्तेमाल हो रही सोयाबीन की अब सब्जी भी बन सकेगी। कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिकों ने हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को विकसित किया है। इससे आम आदमी की थाली और पौष्टिक होगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बालाघाट के चावल चिन्नौर किस्म को जीआई टैग मिलने पर प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार ज्ञापित किया है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रचलित फसलों की 35 नई आधुनिक किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प पूरा करने में देश के साथ मध्यप्रदेश के कृषि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह फसलें किसानों को आत्म-निर्भर बनाने में सफल होंगी। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई फसलों की यह नई किस्में छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होंगी।

प्रदेश भर में तैयार हो रहे नमो उपवन

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से चल रहे सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत 29 सितंबर से 3 दिवसीय नमो उपवन के अंतर्गत पार्टी

पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडल स्तर पर 71 पौधे लगाकर नमो उपवन तैयार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अभियान के पहले दिन बागली विधानसभा और उज्जैन में, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं सह संगठन महामंत्री हितानंद जी ने भोपाल के साकेत नगर मंडल में पौधारोपण कर नमो उपवन अभियान की शुरुआत की। गुरुवार को नमो उपवन अभियान के दूसरे दिन प्रदेशभर में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं ने 71 पौधे रोपकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। भोपाल में पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने महाराणा प्रताप मंडल में नमो उपवन में पौधोरापण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

माशिमं के जनसंपर्क अधिकारी चौरसिया हुए सेवानिवृत्त

भोपाल । माध्यमिक शिक्षा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी एसके चौरसिया गुरुवार

को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी से सौजन्य भेंट कर उनके मार्गदर्शी नेतृत्व के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती शमी ने, विभाग में श्री चौरसिया की उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति साधुवाद दिए एवं उनके सुखमय और स्वस्थ जीवन पथ की शुभकामनाएं भी दीं।

जोबट एसडीएम का तबादला करने की मांग

भोपाल । अलीराजपुर जिला की जोबट में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। जोबट विधानसभा क्षेत्र में श्यामवीर नरवरिया एसडीएम के रूप में पदस्थ है जिनका स्थानानंतरण करने की मांग कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। धनोपिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि जोबट विधानसभा से श्री नरवरिया का अन्यंत्र स्थानांतरण किया जाए। क्योंकि वह केंद सरकार में राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद हैं, इस कारण जोबट में उपचुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है तथा मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने हेतु दबाव बनाया जा सकता है, उन्हें प्रलोभन दिया जा सकता है। जिससे मतदान निष्पक्ष रूप से संपन्न होने में संदेहास्पद स्थिति निर्मित होगी। धनोपिया ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए श्री नरवरिया का स्थानांतरण अन्यंत्र किया जाए।

नियम विरुद्ध नियुक्ति तत्काल निरस्त करे सरकार

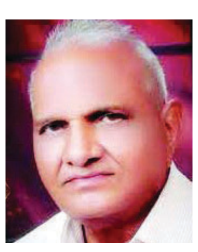

भोपाल । प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव न कराकर शासकीय/अशाकीय लोगों को प्रशासक/सलाहकार के रूप में बैठाकर संस्थाओं में नियम विरुद्ध नियुक्तियां की जाकर सहकारी संस्थाओं के प्रजातांत्रिक ताने-बाने को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। यह आरोप प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने लगाया है। श्री यादव ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्था अपेक्स बैंक में 80 वर्षीय एलडी पंडित जो कि अपेक्स बैंक से वर्ष 2007 में स्वेच्छिक सेवानिवृत्त लिए हैं, की 75 हजार रुपए प्रतिमाह पर सलाहकार नियुक्त किया है। जबकि सेवानियम में किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी को 65 वर्ष की आयु के बाद किसी भी रूप में संविदा पर रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी एलडी पंडित को नियम विरुद्ध अपेक्स बैंक में नियुक्ति दी जाकर संस्थाओं को चारागाह बनाकर जनधन का दुरुपयोग किया जाकर किसानों की सहकारी संस्थाओं को क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अत: पंडित की अवैध नियुक्ति को समाप्त कर उनके खिलाफ वसूली एवं अपराधिक कार्रवाई की जावे। श्री यादव ने नियम विरुद्ध नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किये जाने की मुख्यमंत्री से मांग की है ताकि किसानों की सहकारी संस्थाओं में हो रही जन-धन की बर्बादी को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात

प्रधानमंत्री ने की सीएम राइज स्कूल समेत अन्य योजनाओं की सराहना

किसानों की आय बढ़ाने व अन्य विषयों पर हुई सार्थक चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश में चंदन की खेती करने और व्हाउचर सिस्टम लागू करने का दिया सुझाव

भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश शासन की सीएम राईज स्कूल योजना, सुशासन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में टीकाकरण अभियानों की सफलता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की कोविड नियंत्रण, कोविड टीकाकरण, वर्षा की स्थिति सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्यप्रदेश में कोविड की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है और इस समय केवल 127 ही एक्टिव प्रकरण हैं। प्रदेश में 88 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज और 27 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को सीएम राईज स्कूल योजना से अवगत कराया। उन्हें बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 350 विद्यालय खोले जा रहे हैं जो खेल के मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं से संपन्न होंगे और विद्यार्थियों के लिए बसों से आने-जाने की सुविधा होगी। साथ ही शिक्षकों का चयन वर्तमान शिक्षकों में से ही परीक्षा के आधार पर किया जाउगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के इस नए शिक्षा प्रयोग की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है जिसकी तैयारी में मध्यप्रदेश कोदो-कुटकी जैसे पौष्टिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि प्रदेश में अत्यधिक और कम उत्पादन वाली फसलों के बीच संतुलन बनाते हुए मध्यप्रदेश को एक मॉडल राज्य बनाया जाएगा। जिसमें निर्यात की अधिक संभावना वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। फसलों के विविधीकरण और व्यवसायिक खेती पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में चंदन की खेती करने का सुझाव दिया, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मप्र में व्हाउचर सिस्टम लागू करने का सुझाव भी दिया।

मप्र में 28 कंपनियों ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया है आवेदन

राज्य शासन की एथेनॉल पालिसी के बारे में चर्चा के दौरान श्री चौहान ने बताया कि 28 कंपनियों ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रदेश में आवेदन किया है। अनाज के आवश्यकता से अधिक उत्पादन का उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुझाव दिया कि विकास कार्यों के लिए ली गई वन भूमि के स्थान पर दुगनी राजस्व भूमि देनी पड़ती है, जिसके स्थान पर यदि बिगड़े वनों पर तीन गुना अधिक वन लगाने का दायित्व दिया जाए तो वन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी।

प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर हुई मंत्रणा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री श्री मोदी से मंत्रणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर दीनदयाल समितियों का गठन किया गया है जो विकास योजनाओं की उचित निगरानी कर रही हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जानकारी दी कि वे जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद कर हितग्राहियों को प्राप्त लाभों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। उनके इस प्रयास को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा। श्री चौहान ने राज्य के मंत्रियों और उनके स्टाफ की क्षमता निर्माण के लिए कर्मयोगी अभियान पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में व्हाउचर सिस्टम लागू करने का भी सुझाव दिया।

शिवराज सिंह ने पीएम को दिया तीन कार्यक्रमों का न्यौता

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिले में 100 प्रतिशत अधिकार पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। साथ ही, मध्यप्रदेश के अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लोकार्पण और 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के लिए भी मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया। बैठक में आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल हेल्थ मिशन, सिकलसेल एनिमिया मिशन पर भी चर्चा हुई। श्री चौहान ने प्रदेश में खाद आपूर्ति की स्थिति से भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया।

बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग

भोपाल (एजेंसी)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के किसानों की ओर से हृदय से अभिनंदन किया है।

सीएम श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को न केवल उनका हक मिला है, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मध्यप्रदेश पूरी निष्ठा एवं सामर्थ्य के साथ प्रयासरत है। निस्संदेह बालाघाट के चिन्नौर चावल को जी आई टैग मिलने से इस ध्येय की प्राप्ति को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे निश्चय ही किसानों की आय में ब?त्तरी के साथ मध्यप्रदेश की समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह जीआई टैग प्रगति यात्रा में शामिल मध्यप्रदेश के किसानों को वैश्विक बाजार प्रदान कर उनके जीवन में एक नया प्रकाश लायेगा।

सीएम ने पीएम और केंद्रीय मंत्रियों को दिया धन्यवाद

सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के अनुभवों का लाभ लेते रहना चाहिए : खाड़े

भोपाल (एजेंसी)। जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुदाम खाड़े ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों और कर्मचरियों के अनुभव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय-समय पर उनके अनुभवों का लाभ विभाग को लेते रहना चाहिए। श्री खाड़े गुरुवार को विभाग के जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र व्यास एवं कर्मचारी गंगा सिंह व कांतिदेवी की सेवानिवृत्ति पर जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित विदाई समारोह में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा विभाग में कोई आ तो नहीं रहा (यानी भर्ती नहीं हो रही), लेकिन अधिकारी-कर्मचारी जा ही (सेवानिवृत्त) रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में कोरोना के कारण कई साथियों को खोया है, लेकिन कभी भी हमारा कदम रूका नहीं है...प्रशंसनीय है। छुट्टी तो दिमागी खेल है... संडे और अवकाश के दिनों में भी कई अधिकारी काम करते रहते हैं। इस दौरान मीडिया साथियों (पत्रकारों) की भी करीब पौने 11 करोड़ रुपए की मदद की गई है। उन्होंने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि व्यास जी ने 39 साल से अधिक समय तक विभाग में सेवाएं दीं यह बहुत बड़ा कालखंड है। अब उन्हें छूट गए कार्यों को कर लेना चाहिए। उन्होंने व्यास सहित तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर विभाग के संचालक आशुतोष प्रताप सिंह, अपर संचालक सुरेश गुप्ता एवं एचएल चौधरी भी मंचासीन थे।

समिट में साइबर क्राइम रोकथाम की नीति निर्माण पर हुआ विचार-विमर्श

भोपाल (एजेंसी)। मप्र पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस (सीआईआईएस) समिट-2021 में साइबर क्राइम रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विवेचना के लिए नीति निर्माण पर विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। मध्यप्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तरप्रदेश तथा झारखंड के उच्च पुलिस अधिकारियों के बीच साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पहचान के लिए किए गए नवाचारों पर पैनल डिस्कशन हुआ।

प्रथम सत्र में इंटरपोल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. मदन एम. ओबेराय ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विस्तृत जानकारी दी। द्वितीय सत्र में तृतीय सत्र में एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने भविष्य में साइबर क्राइम की चुनौतियों से अवगत कराया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साइबर अंयेश राय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिगं पोर्टल की जानकारी दी। अंतिम सत्र में चेयरमैन, कॉर्पोरेट क्राइम एंड डिजीटल इविडेंस के जेम्स इमरसन ने साइबर इंवेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस पॉलिसी मैकिंग चैलेन्जेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स विषय पर जानकारी साझा की।

समिट का समापन आज : 10 दिवसीय सीआईआईएस समिट-2021 का समापन एक अक्टूबर सुबह 10 बजे मप्र पुलिस अकादमी भौरी में होगा। समापन कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य आतिथि के रूप में शामिल होंगे।

महिलाओं को शिक्षित बनाने चार 'ई' योजना पर काम करेगा महिला मोर्चा

भोपाल (एजेंसी)। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित, स्वाबलंबी और सशक्त बनाने के लिए महिला मोर्चा चार 'ई' योजना पर काम करेगा।

मीडिया से रूबरू हुई माया नरोलिया

श्रीमती नारोलिया ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला मोर्चा की देहरादून में हुई राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में तय किया गया है कि मोर्चा अधिक से अधिक महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए चार 'ई' यानी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंपलॉयमेंट और एम्पॉवरमेंट की योजना पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की कई योजनाएं चल रही हैं और कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने 'ई' केंद्र योजना के संबंध में बताया कि इस योजना की मॉनीटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर एक केंद्र बनाया जाएगा। मोर्चा की प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर तक की पदाधिकारी इस योजना में शामिल होंगी। हर पदाधिकारी 75 महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगी और उन्हें शिक्षित, सशक्त बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमशीलता के विकास के लिये प्रयास करेंगी। मोर्चा पदाधिकारी इन महिलाओं, युवतियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ दिलाएंगी।

महिला मोर्चा बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने करेगा काम

श्रीमती नारोलिया ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना शुरू की है, जिसमें प्री स्कूलों के बच्चों को भी मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार छोटे बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराने जा रही है। इस चावल में सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। इसके लिए महिला मोर्चा की बहनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके बाद वे फोर्टिफाइड राइस का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगी। श्रीमती नारोलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार के प्रयासों से प्रदेश के कुपोषित बच्चों में से 47 प्रतिशत अब स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की बहनें राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए घर.घर जाएंगी। सर्वे करेंगी और कुपोषित बच्चों की खोज कर उनका उपचार शुरू कराएंगी, ताकि उन्हें कुपोषण मुक्त किया जा सके। श्रीमती नारोलिया ने कहा कि सेवा और समर्पण अभियान में महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी रही है। इसी तरह आगामी 07 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अन्न उत्सव में मोर्चा की बहनें सभी 25435 राशन दुकानों पर उपस्थित रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राशन दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 100 धन्यवाद पत्र लिखे जा रहे हैं। मोर्चा की बहनें इन धन्यवाद पत्रों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी।

दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा परिक्रमा पर आधारित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा

नर्मदा परिक्रमा में अमित शाह ने भी किया था मेरा सहयोग

भोपाल, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि लगभग चार वर्ष पहले उनकी 'नर्मदा परिक्रमा' के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उनकी भरपूर मदद की थी। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर आलोचक श्री सिंह ने उनकी नर्मदा परिक्रमा पर आधारित पुस्तक 'नर्मदा का पथिक' के विमोचन के दौरान अपने संबोधन में इस रहस्य से पर्दा उठाया। श्री सिंह के साथ जुड़े रहे ओपी शर्मा द्वारा लिखित इस पुस्तक के विमोचन समारोह में उनकी पत्नी अमृता राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, रामेश्वर नीखरा और सुरेश पचौरी भी मौजूद थे।

श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने अपने दल बल के साथ नर्मदा परिक्रमा के तहत महाराष्ट्र की सीमा पार कर गुजरात की सीमा में प्रवेश किया था। उस समय रात हो चुकी थी और हमें घने जंगलों से निकलना था। तभी वन विभाग का एक अधिकारी आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि अमित शाह (वरिष्ठ भाजपा नेता) के निर्देश पर वह यहां पहुंचे हैं और उन्होंने (श्री शाह ने) निर्देश दिए हैं कि श्री सिंह की यात्रा के दौरान उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि उस समय गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे थे और वे श्री शाह के सबसे बड़े आलोचक हैं। इसके बावजूद उन्होंने पूरा सहयोग किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि उनकी श्री शाह से आज तक 'वन टू वन' भेंट नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने जो सहयोग किया था, उन्होंने उनके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त किया था और उन्हें बाकायदा संदेश भिजवाया। श्री सिंह ने कहा कि इसी तरह वे संघ (आरएसएस) के भी वे बड़े आलोचक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी परिक्रमा के दौरान मदद की।

संकल्प का दस्तावेज है नर्मदा के पथिक

पुस्तक का विमोचन मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसरोवर ऑडिटोरियम में एक गरिमामय समारोह में किया गया। पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा ने स्वागत भाषण दिया। नर्मदा के पथिक पुस्तक के लेखक ओपी शर्मा ने पुस्तक का परिचय और उससे संबंधित वृत्तांत सुनाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी व नर्मदा परिक्रमा में सहयात्री रहीं अमृता राय ने अपने उद्बोधन में नर्मदा परिक्रमा के दौरान के अनुभव सुनाए साथ ही पर्यावरण संरक्षण की बात की। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को आशीर्वाद देने पधारे सभी साधु-महात्माओं और साध्वियों ने आशीर्वचन दिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपने उद्बोधन में बरमान की महिमा का वर्णन किया। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि आज का दिन दिग्विजय सिंह का है और हम सभी उन्हीं को सुनने आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने दिग्विजय सिंह की तुलना महात्मा गांधी से कर बताया कि जिस तरह महात्मा गांधी चलते हुए कभी नहीं थकते थे उसी तरह दिग्विजय सिंह ने इतनी लंबी दूरी की परिक्रमा कर सभी को प्रेरणा दी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अपने संबोधन में कहा कि दिग्विजय सिंह ने परिक्रमा के संकल्प के बारे में मुझे बताया था। श्री तन्खा ने कहा कि कोई माने या न माने मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा करने के बाद ही बनी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लेखक ओपी शर्मा की सराहना की। उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ चले सभी परिक्रमा वासी जो कार्यक्रम में उपस्थित थे उनको बधाई दी।

अपने रंग की वजह से हिना खान को झेलना पड़ा था रिजेक्शन

टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा के किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। हाल ही में हिना का एक नया म्यूजिक वीडियो 'मैं भी बर्बाद' रिलीज हुआ है। हिना खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर को लेकर चौंकाने वाली बात बताई है। उन्होंने खुलासा सांवले रंग की वजह से उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक प्रोजेक्ट में केवल इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि वे बहुत ज्यादा गोरी नहीं थीं। हिना खान से जब पूछा पूछा गया कि वो रिजेक्शन से कैसे निपटती है। इस पर उन्होंने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक प्रोजेक्ट को क्रैक नहीं कर सकी क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं दिख रही थी। मैं कश्मीरी हूं और मैं वहां की भाषा बोल सकती हूं लेकिन मुझे कास्ट नहीं किया गया क्योंकि मेरा रंग सांवला है और मैं बहुत गोरी नहीं हूं। उन्होंने कहा, टीम और किरदार के लिए यही जरूरी था। मुझे बहुत बुरा लगा था। जब आप भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हों और आप किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हों और सिर्फ कश्मीरी दिखें ना इसलिए आपको रोल न मिले। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और न हार मानी। मैंने हमेशा कोशिश जारी रखी। हिना खान ने टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। वह कई सीरियल्स, फिल्म और म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी है। उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म 'हैक्ड' से बॉलीवुड में एंट्री की थी।

कंगना रनौत ने थलाइवी के बाद कम किया 20 किलो वजन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो रही है यह समस्या

बॉलीवुड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थलाइवी' में अपने दमदार अभिनय को लेकर अभिनेत्री प्रशंसा बटोर रही हैं। फिल्म थलाइवी में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भूमिका निभाने वाली क्वीन स्टार को हर तरफ से प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने हाल ही में फिल्म को लेकर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि –यह बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि जय ललिता की भूमिका में फिट होने के लिए अभिनेत्री को 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ा ।और आने वाले अपने प्रोजेक्ट ' धाकड़' के लिए उन्हें 6 महीने में अपना वजन कम भी करना पड़ा। अभिनेत्री ने बताया कि इस बदलाव से मेरे शरीर में बहुत सी चीजें खराब हो गई हैं। साथ ही उन्हें इस बदलाव से शरीर पर परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स भी मिले हैं ।उन्होंने कहा– 'कला एक कीमत के साथ जीवन में आती है' और अक्सर कलाकार खुद भी एक थलाइवी होते हैं। आपको बता दें कि थलाइवी एक भारतीय अभिनेत्री, राजनेता जयललिता के जीवन पर आधारित एक ड्रामा फिल्म है। जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत जयललिता के रूप में और एमजी रामचंद्रन के रूप में अरविंद स्वामी हैं। विजय द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। अभिनेत्री के वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना 'धाकड़' की शूटिंग के बाद अब फिल्म 'तेजस' की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म तेजस में वह एक भारतीय वायु सेना के पायलट की भूमिका में नजर आएंगी। सर्वेश मेवाड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म एक साहसी और भयंकर लड़ाकू पायलट की कहानी है।

कार्तिक आर्यन ने राम माधवानी की धमाका का मूड प्रोमो किया रिलीज

अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी आने वाली फिल्म धमाका का मूड प्रोमो रिलीज कर दिया है। यह फिल्म के प्रमोशनल बिल्ड–अप का हिस्सा है। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर मूड प्रोमो साझा किया और इसे कैप्शन दिया, ट्रेलर अभी बाकी। वीडियो में, कार्तिक को घर में नजरबंद होने के बारे में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली खबर से जगाया जाता है। इसके तुरंत बाद, स्क्रीन से एक आवाज आने लगती है, जिसमें कार्तिक को निदेशरें का पालन करने और खुद को एक कुर्सी से बांधने के लिए कहा जाता है। वीडियो एक समाचार कक्ष में समाप्त होता है, जहां से कार्तिक अपने कैरेक्टर अर्जुन पाठक, एक टेलीविजन एंकर का परिचय देते है। धमाका 2013 में आई कोरियाई फिल्म द टेरर लाइव की आधिकारिक रीमेक है। नीरजा और हाल फिलहाल में रिलीज हुई आर्या फेम राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म में मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान भी हैं। यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

विक्की कौशल की फिल्म 'सरदार उधम' का टीजर आया सामने

विक्की कौशल ने सोमवार को अपनी आने वाली फिल्म सरदार उधम का टीजर शेयर किया। वीडियो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह के इर्द–गिर्द केंद्रित एक दिलचस्प कहानी है। क्लिप में हम कौशल के चरित्र को एक दस्तावेज़ के साथ जोड़ते हुए देखते हैं। प्रोमो वीडियो को अभिनेता के इंस्टाग्राम पर एक छोटे से नोट के साथ साझा किया गया, जिसमें लिखा था, 'शहीद भगत सिंह की जयंती पर, मुझे आपके सहयोगी सरदार उधम सिंह– एक आदमी, कई उपनामों की कहानी लाने पर गर्व है। पेश है #SardarUdham का टीज़र।'

फिल्म 'सरदार उधम' 16अक्टूबर को रिलीज होगी

शुजित सरकार निर्देशित फिल्म 'सरदार उधम' 16अक्टूबर को रिलीज होगी। अमेजन प्राइम ने सोमवार को यह घोषणा की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है जाने माने अभिनेता विक्की कौशल ने। यह फिल्म भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग जनसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। उनके इस साहस ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी।

रिलीज हुआ फिल्म सरदार उधम टीजर

फिल्म निर्माताओं ने फिल्म रिलीज होने की तारीख एक टीजर जारी करके दी। फिल्म का निर्माण 'राइजिंग सन फिल्म्स' ने 'किनो वर्क्स' के साथ मिल कर किया है। अभिनेता विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म का टीजर जारी किया। उन्होंने लिखा,'' शहीद भगत सिंह की जयंती पर मुझे उनके साथी सरदार उधम सिंह की कहानी पेश करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

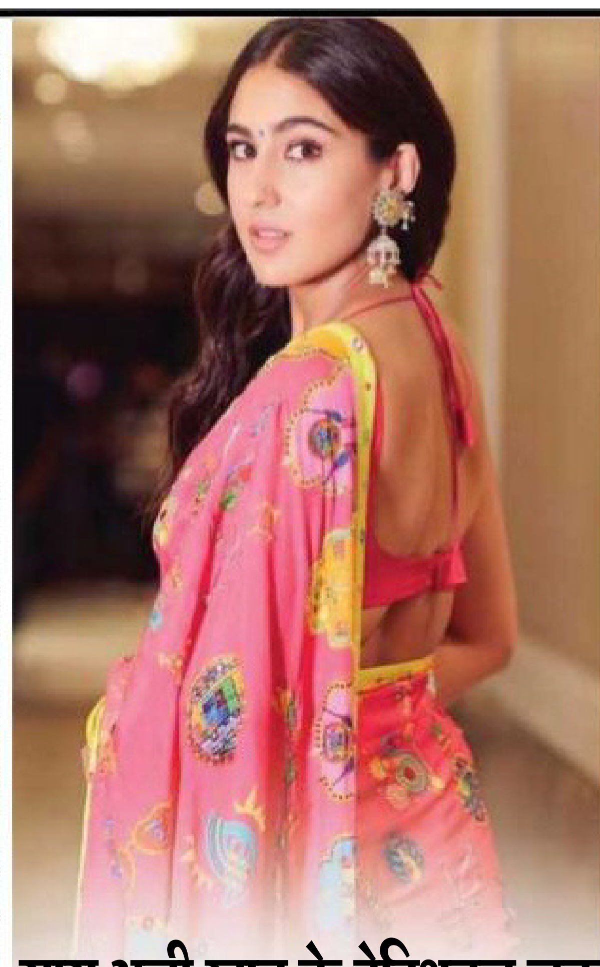

सारा अली खान के ट्रेडिशनल लुक ने जीता फैंस का दिल, साड़ी पहने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार सारा अली खान ने साड़ी पहने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है। सारा तस्वीरों में गाजीरी रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहने नजर आ रही हैं। सारा अली खान की ये साड़ी मदर थीम पर है। साड़ी पर अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक डायलॉग लिखा है– 'मेरे पास मां है'। उनकी साड़ी पर 'ठंड रख' जैसा मजेदार फ्रेज भी प्रि?टेड है। सारा ने साड़ी के साथ पिंक कलर के मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है। माथे पर छोटी सी बिंदी, सॉफ्ट कर्ल हेयर, सिल्वर झुमके और मैचिंग चूड़ियों ने एक्ट्रेस का लुक काफी खूबसूरत लग रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा अली खान ने कैप्शन में लिखा है, 'क्योंकि साड़ी में नारी हमेशा ही प्यारी लगती हैं।' फैंस का सारा का यह ट्रेडिशनल लुक काफी पसंद आ रहा हैं। वह कमेंट करके एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान आखिरी बार वरुण धवन के साथ फिल्म 'कुली नंबर 1' में नजर आई थीं। वह जल्द ही अक्षय कुमार और धनुष के साथ फिल्म 'अतरंगी रे' में दिखेंगी।

आरएसएस की तुलना तालिबान से करना जावेद अतर को पड़ रहा भारी, कोर्ट ने भेजा कारण बताओ नोटिस

बॉलीवुड के फेमस गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर जाते हैं। बीते दिनों जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान के साथ आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की तुलना कर दी थी। इसके बाद से उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जावेद अख्तर के खिलाफ एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह केस ठाणे कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने जावेद अख्तर को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 12 नवंबर को मामले की अगली तारीख में पेश होने का निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार इस मामले से जुड़े वकील संतोष दुबे का कहना था कि अगर जावेद अख्तर बिना शर्त लिखित माफी' मांगने और नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर जवाब देने में विफल हुए तो वह अख्तर से 100 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में मांगते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। वकील का दावा था कि इस तरह की बयानबाजी करके जावेद अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध किया है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, उनमें और तालिबान में क्या अंतर है? उनकी जमीन मजबूत हो रही है और वे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जावेद अख्तर के इस बयान के बाद से ही जमकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों बीजेपी ने गीतकार के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। कई बीजेपी नेताओं ने जावेद अख्तर को मांफी मांगने के लिए कहा था। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जावेद अख्तर के इस बयान पर विरोध जताया था।

हेजलवुड और ब्रावो का कमाल, चेन्नई ने सनराइजर्स को 134 रन पर रोका

एजेंसी ■ शारजाह

हेजलवुड ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए जो आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ब्रावो ने 17 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सनराइजर्स की तरफ से ऋद्धिमान साहा ने सर्वाधिक 44 रन बनाए लेकिन इसके लिए उन्होंने 46 गेंदें खेली।

जोश हेजलवुड और ड्वेन ब्रावो की अगुवाई में गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुरुवार को यहां सात विकेट पर 134 रन ही बनाने दिए।
हेजलवुड ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए जो आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ब्रावो ने 17 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सनराइजर्स की तरफ से ऋद्धिमान साहा ने सर्वाधिक 44 रन बनाए लेकिन इसके लिए उन्होंने 46 गेंदें खेली। पहले दो ओवर में पांच रन और फिर सलामी बल्लेबाज जैसन रॉय (दो) का विकेट। स्वाभाविक था कि सनराइजर्स ऐसी शुरुआत नहीं चाहता था। साहा ने दीपक चाहर के पारी के तीसरे ओवर में दो छक्के लगाए जिससे सनराइजर्स पावरप्ले में एक विकेट पर 41 रन तक पहुंचा लेकिन इसके तुरंत बाद उसने कप्तान केन विलियमसन (11) का विकेट गंवा दिया जिन्हें ब्रावो ने पगबाधा आउट किया। साहा जब 29 रन पर थे तब उन्होंने प्वाइंट पर आसान कैच दे दिया था लेकिन शार्दुल ठाकुर (37 रन देकर एक) की यह गेंद नोबॉल निकल गई। स्कोर हालांकि कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा था और 10 ओवर में केवल 63 रन बने थे, जिसके बाद ब्रावो ने प्रियम गर्ग (सात) का संघर्ष समाप्त किया। साहा ने जब धोनी को आसान कैच थमाया तो रविंद्र जडेजा (तीन ओवर में 14 रन देकर एक) ने नोबॉल नहीं की थी। बीच में 48 गेंद तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। छठे ओवर के बाद 13वें ओवर में जाकर गेंद ने सीमा रेखा के दर्शन किए। अब्दुल समद (18) ने ठाकुर पर चौका लगाने के बाद हेजलवुड पर छक्का भी लगाया। अभिषेक शर्मा (18) ने भी हेजलवुड के अगले ओवर में छक्का लगाया लेकिन इस आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने इन दोनों बल्लेबाजों को तीन गेंद के अंदर पवेलियन की राह दिखा दी। जैसन होल्डर (पांच) के आउट होने के बाद राशिद खान (13 गेंद पर नाबाद 17) ने डेथ ओवरों में कुछ रन जुटाए।

एक नजर

युवेंटस ने गत चैम्पियन चेलसी को हराया

तूरिन। इतालवी क्लब युवेंटस ने खिलाड़ियों की फिटनेस समस्याओं से परेशान गत चैम्पियन चेलसी को चैम्पियंस लीग फुटबॉल के मुकाबले में । . 0 से हरा दिया और चेलसी के स्टार फुटबॉलर रोमेलू लुकाकू भी कोई कमाल नहीं कर सके। दूसरे हाफ के दस सेकंड के भीतर फॉरवर्ड फेडरिको चिएसा ने फेडरिको बर्नाडेस्ची से मिली गेंद पर गोल करके युवेंटस को बढत दिलाई। चेलसी के कोच थॉमस टूचेल ने कहा , दूसरे हाफ के शुरूआती सेकंड में ही इस तरह का आसान गोल गंवाना समझ से परे है। डिफेंस की चूक का खामियाजा तो भुगतना ही था। अगस्त में रिकॉर्ड 135 मिलियन डॉलर के करार पर चेलसी से जुड़े बेल्जियम के स्ट्राइकर लुकाकू ने 75वें मिनट में हेडर लगाया जो निशाना चूक गया। इसके आठ मिनट बाद भी उनका शॉट निशाने पर नहीं लगा। युवेंटस इस जीत के बाद ग्रुप एच में पूरे छह अंक लेकर शीर्ष पर है। चेलसी और सेंट पीटर्सबर्ग के तीन तीन अंक हैं।

लेवांडोवस्की के दो गोल से बायर्न ने डायनामो कीव को हराया

म्युनिख। रॉबर्ट लेवांडोवस्की के दो गोल की मदद से बायर्न म्युनिख ने चैम्पियंस लीग फुटबॉल में उक्रेन के क्लब डायनामो कीव को गुरूवार को 5 . 0 से हरा दिया। बायर्न ने सभी प्रतिस्पर्धाओं में लगातार नौवें मैच में तीन से अधिक गोल किए हैं। लेवांडोवस्की नौ मैचों में 13 गोल कर चुके हैं। बायर्न ने पहले मैच में बार्सीलोना को 3 . 0 से हराया था। अब उसका सामना बेनफिक्का से होगा जिसने बार्सीलोना को 3 . 0 से मात दी। दिसंबर 2019 के बाद बायर्न ने पहली बार अपने मैदान पर दर्शकों के सामने खेला है। पिछले सत्र में यूरोपीय लीग के सारे मैच खाली स्टेडियम में खेले थे।

संक्षिप्त खबर

तोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रूपिंदर और लाकड़ा ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे स्टार ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह और डिफेंडर बीरेंद्र लाकड़ा ने युवाओं के लिए रास्ता बनाने की कवायद में गुरूवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रूपिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की घोषणा की जबकि लाकड़ा के संन्यास का ऐलान हॉकी इंडिया ने किया। तोक्यो ओलंपिक में भारत के उपकप्तान रहे लाकड़ा ने हालांकि बाद में अपने फेसबुक पेज पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी बात कही। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि दोनों खिलाड़ियों को बता दिया गया था कि अगले सप्ताह से बेंगलुरू में शुरू हो रहे राष्ट्रीय शिविर में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। देश के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में शामिल किए जाने वाले 30 साल के रूपिंदर ने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बॉब के नाम से मशहूर रूपिंदर ने तोक्यो ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीतने के अभियान के दौरान चार गोल दागे थे जिसमें तीसरे स्थान के प्ले आफ में जर्मनी के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक पर किया गोल भी शामिल था। रूपिंदर का यह फैसला हैरानी भरा है क्योंकि उनकी फिटनेस और फॉर्म को देखते हुए स्पष्ट तौर पर वह कुछ और साल आसानी से खेल सकते थे। रूपिंदर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बयान मे लिखा , इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ महीने मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन रहे। मैंने अपने जीवन के कुछ शानदार अनुभव जिनके साथ साझा किए टीम के अपने उन साथियों के साथ तोक्यो में पोडियम पर खड़े होना ऐसा अहसास था जिसे मैं हमेशा सहेजकर रखूंगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि अब समय आ गया है जब युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उस आनंद की अनुभूति का अवसर दिया जाए जो भारत के लिए खेलते हुए मैं पिछले 13 साल से अनुभव कर रहा हूं। वहीं लाकड़ा के बारे में हॉकी इंडिया ने ट्वीट किया , मजबूत डिफेंडर और भारतीय हॉकी टीम के सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में से एक ओडिशा के स्टार लाकड़ा ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने का फैसला लिया है। हैप्पी रिटायरमेंट बीरेंद्र लाकड़ा। लाकड़ा ने बाद में फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखकर कहा , पिछले कुछ सप्ताह से मैं हॉकी में अब तक के अपने सफर पर आत्ममंथन कर रहा था। भारत के लिए खेलना और भारतीय टीम की जर्सी पहनने से ज्यादा खुशी और गर्व मुझे किसी बात से नहीं मिला। अब समय आ गया है कि अगली पीढी के युवा खिलाड़ी भारत के लिए खेलने के अहसास को जी सकें। उन्होंने आगे कहा , पिछले 11 साल में देश के लिए 201 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद मैने भारतीय हॉकी टीम से विदा लेने का फैसला किया है।

इतने शानदार खिलाड़ियों के साथ फिर ड्रेसिंग रूम साझा नहीं कर पाने के अहसास की अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं उन्हें भारतीय हॉकी को आगे ले जाने के लिए शुभकामना देता हूं चूंकि अगले ओलंपिक तीन साल बाद ही हैं। ओडिशा के इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा , मैने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए अपने कैरियर में कई उतार चढाव देखे लेकिन ओलंपिक कांस्य पदक जीतने से बढकर कुछ नहीं।

केकेआर और पंजाब के मुकाबले में नजरें वेंकटेश और बिश्नोई पर

कोलकाता के हरफनमौला खिलाड़ी वेंक्टेश ने अनुशासित तेज गेंदबाजी के सामने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खीचा है। वहीं बिश्नोई की क्लाई की स्पिन ने पिछले दो सत्र में नामी गिरामी बल्लेबाजों को भी परेशान किया है।

एजेंसी ■ दुबई

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच शुक्रवार को होने वाले आईपीएल के मैच में नजरें वेंकटेश अय्यर की शानदार बल्लेबाजी और रवि बिश्नोई की बेहतरीन गेंदबाजी के मुकाबले पर भी रहेंगी। कोलकाता के हरफनमौला खिलाड़ी वेंकटेश ने अनुशासित तेज गेंदबाजी के सामने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। वहीं बिश्नोई की क्लाई की स्पिन ने पिछले दो सत्र में नामी गिरामी बल्लेबाजों को भी परेशान किया है। के एल राहुल की पंजाब टीम के लिए प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के मकसद से यह करो या मरो का मुकाबला होगा। राहुल ने मुंबई इंडियंस के हाथों मिली हार के बाद स्वीकार किया कि दबाव में उनकी टीम अच्छा नहीं खेल पा रही और उन्हें प्रदर्शन में सुधार करना होगा। मध्यक्रम के खराब फॉर्म का भी असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा है। राहुल (422 रन) और मयंक अग्रवाल (332) को छोड़कर कोई बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सका है। क्रिस गेल ने 10 मैचों में सिर्फ 193 रन बनाए हैं। वहीं निकोलस पूरन दस मैचों में 70 रन ही बना सके हैं।भारतीय खिलाड़ियों में एम शाहरूख खान और दीपक हुड्डा मौकों का फायदा नहीं उठा सके हैं।

बल्लेबाजों की नाकामी के बीच सुनील नारायण और वरूण चक्रवर्ती जैसे धुरंधर स्पिनरों का धीमी पिच पर सामना करना और कठिन होगा। इन दोनों के आठ ओवर मैच की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। वहीं पंजाब के लिए बिश्नोई (नौ विकेट) को छोड़कर कोई गेंदबाज बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सका। मोहम्मद शमी ने 14 और अर्शदीप सिंह ने 13 विकेट जरूर लिए लेकिन दोनों महंगे साबित हुए हैं। केकेआर के लिए वेंकटेश 144 प्लस के स्ट्राइक रेट से 126 रन बना चुके हैं। अगर वह शमी और अर्शदीप का पहला स्पैल खेल जाते हैं तो यह देखना रोचक होगा कि वह बिश्नोई और हरप्रीत बरार का सामना कैसे करते हैं। केकेआर ने नीतिश राणा को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजकर भी सही फैसला लिया है चूंकि वह स्पिन को कप्तान ईयोन मोर्गन से बेहतर खेलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली जीत में उन्हें इस फैसले का फायदा भी मिला।

टीमें :

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, गुरकीरत सिंह मान, करूण नायर, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्युसन, पवन नेगी, एम प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वारियर , शिवम दुबे, टिम साउथी, वैभव अरोड़ा, वरूण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, शाकिब अल हसन, सुनील नारायण, वेंक्टेश अय्यर, शेल्डन जैकसन और टिम सीफर्ट।

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल, शाहरुख खान, मोहम्मद शमी, नाथन एलिस, आदिल राशिद, मुरुगन अश्विन, हरप्रीत बराड़, मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस जॉर्डन, एडेन मार्कराम, मनदीप सिंह, दर्शन नालकांडे , प्रभसिमरन सिंह, रवि बिश्नोई, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलन, सौरभ कुमार, जलज सक्सेना।

मैच शाम 7.30 से शुरू होगा।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम मैत्री मैचों के लिए यूएई पहुंची

एजेंसी ■ दुबई

भारतीय महिला फुटबॉल टीम शनिवार से यूएई और बहरीन में होने वाले मैत्री मैचों के लिए गुरुवार को यहां पहुंच गई। भारत में अगले साल होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप के लिए टीम की तैयारियों को देखते हुए इन मैत्री मैचों की योजना बनाई गई है। भारतीय टीम झारखंड सरकार की मदद से जमशेदपुर में शिविर लगाया था। सहयोगी स्टाफ के साथ भारत की 23 सदस्ईय टीम जमशेदपुर से नई दिल्ली पहुंची और फिर दुबई के लिए रवाना हुई। टीम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ दो अक्टूबर को मैत्री मैच खेलने के बाद चार अक्टूबर को ट्यूनिशिया के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम इसके बाद बहरीन रवाना होगी जहां उसे 10 अक्टूबर को मेजबान टीम जबकि 13 अक्टूबर को चीनी ताइपे का सामना करना है। मुख्य कोच थॉमस डेनेर्बी ने कहा, एशिया कप की तैयारी के लिए मैच खेलने का मौका मिलने से लड़कियां उत्साहित हैं। हमने पिछले एक महीने जमशेदपुर में कड़ी ट्रेनिंग की और अब हम कुछ कड़े प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ स्वयं को परखने के लिए तैयार हैं। कप्तान और सेंटर बैक आशालता देवी ने महामारी के बीच शिविर और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमें पता है कि अभी स्थिति आसान नहीं है लेकिन एशिया कप की तैयारी के लिए जिस तरह हर चीज का इंतजाम किया गया वह शानदार है। आशालता ने कहा, झारखंड सरकार ने शीर्ष सुविधाओं के साथ शिविर का आयोजन किया, कड़ी टीमों के खिलाफ मैचों का कार्यक्रम बनाया गया, हमें काफ समर्थन मिला।

टीम इस प्रकार है:

गोलकीपर: अदिति चौहान, मेबाम लिनथोइंगाम्बी देवी, श्रेया हुड्डा
डिफेंडर: दालिमा छिब्बर, स्वीटी देवी, रितु रानी, आशालता देवी, रंजना चानू, मिशेल कस्तान्हा, मानिसा पन्ना, एस्टम ओराओन
मिडफील्डर: संगीता बास्फोरे, इंदुमति कथिरेसन, संजू, मार्टिना थोमचोम
फारवर्ड: डेंगमेई ग्रेस, अंजू तमांग, संध्या रंगनाथन, सौम्या गोगुलोथ, मनीषा कल्याण, सुमति कुमार, प्यारी शाशा और रेनु।

रोनाल्डो के गोल से मैनचेस्टर युनाइटेड जीता

एजेंसी ■ मैनचेस्टर

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर युनाइटेड में वापसी के बाद चैम्पियंस लीग में विजई गोल किया और जीत का जश्न जर्सी उतारकर दर्शकों के अभिवादन का जवाब देते हुए मनाया। चैम्पियंस लीग में 178वां मैच खेल रहे रोनाल्डो ने स्टॉपेज टाइम के पांचवें मिनट में गोल दागा। उनके इस गोल की मदद से युनाइटेड ने विलारीयाल को 2 .। से हराया। इस मैच को देखने के लिए महान फर्राटा धावक उसेन बोल्ट भी स्टेडियम में थे जो लाल और सफेद रंग का युनाइटेड का स्कार्फ गले में डालकर बैठे थे। युवेंटस से दूसरी बार युनाइटेड में आए रोनाल्डो का यह पांच मैचों में पांचवां गोल था। यह चैम्पियंस लीग में उनका 136वां गोल था जो एक रिकॉर्ड है। युनाइटेड ने ग्रुप एफ में स्विटजरलैंड की टीम यंग ब्वायज के खिलाफ। . 2 से हार के साथ आगाज किया था।

वर्मा विश्व कप फाइनल के पहले दौर से बाहर

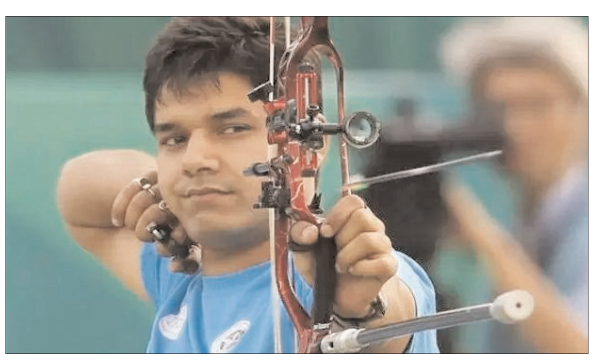

एजेंसी ■ यांकटन (अमेरिका)

भारत के अनुभवी कंपाउंड तीरंदाज अभिषेक वर्मा विश्व कप फाइनल के पहले ही दौर में अमेरिका के ब्राडेन जेलेंथिएन से हारकर बाहर हो गए। दुनिया के चौथे नंबर के तीरंदाज ब्राडेन ने लगातार पांच परफेक्ट 10 स्कोर किया जिसके बाद वर्मा वापसी नहीं कर सके। उन्हें 142 . 146 से पराजय का सामना करना पड़ा। एशियाई खेल 2014 के स्वर्ण पदक विजेता वर्मा ने 2015 विश्व कप में रजत पदक जीता था। उन्होंने पेरिस में विश्व कप का तीसरा चरण जीतकर क्वालीफाई किया था। विश्व कप फाइनल 2018 में उन्होंने व्यक्तिगत कांस्य और ज्योति सुरेखा के साथ मिश्रित युगल का रजत पदक जीता था। अब सभी की नजरें अतनु दास और दीपिका कुमारी पर लगी होंगी जो शाम को अपने अभियान का आगाज करेंगे। दास पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जबकि दीपिका सात बार विश्व कप फाइनल खेलकर चार रजत और एक कांस्य जीत चुकी हैं। डोला बनर्जी विश्व कप फाइनल (2007) में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं।

आईपीएल नए बल्लेबाज को अपेक्षा नही रहती कि उसे आते ही यॉर्कर मिलेगी लेकिन मै डालता हूं।

बोतल या जूते रखकर परफेक्ट यॉर्कर डालने का अभ्यास करते हैं आवेश

नई दिल्ली,(एजेंसी) ।

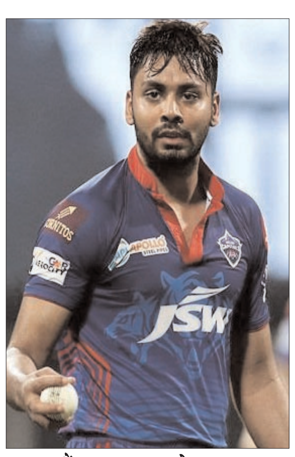

आईपीएल के मौजूदा सत्र में अपने सटीक यॉर्कर और बेहतरीन गेंदबाजी से चर्चा में आए तेज गेंदबाज आवेश खान कैरियर की शुरूआत से इस गेंद पर मेहनत करते आए हैं और इसमें परफेक्शन लाने के लिए बोतल या जूता रखकर घंटों अभ्यास करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल के मौजूदा सत्र में अब तक 11 मैचों में 18 विकेट ले चुके आवेश के साथी गेंदबाज एनरिच नोर्किया ने हाल ही में कहा था कि इस युवा तेज गेंदबाज से सटीक यॉर्कर डालने की कला सीखनी होगी। आईपीएल के इस सत्र के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक इंदौर के इस तेज गेंदबाज ने यएई से भाषा को दिए इंटरव्य में कहा , मैं अभ्यास करते समय 10. 12 यॉर्कर जरूर डालता हूं। यॉर्कर ऐसी गेंद है जिस पर महारत अभ्यास से आती है। मैं बोतल या जूते रखकर गेंद डालता हूं और उस पर गेंद लगती है तो मेरा आत्मविश्वास बढता है और परफेक्शन आती है। उन्होंने कहा , यॉर्कर विकेट लेने वाली गेंद है। दबाव में इसे डालना अहम है क्योंकि यह ही ऐसी गेंद है जिससे मार खाने से बच सकते हैं। नए बल्लेबाज को अपेक्षा नहीं रहती कि उसे आते ही यॉर्कर मिलेगी लेकिन मैं डालता हूं। आईपीएल के इस सत्र में अपने प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा , काफी अच्छा रहा है सफर। मैने हमेशा क्रिकेट शौक या जुनून के तौर पर खेला है और कभी सोचा नहीं था कि इतने ऊंचे स्तर पर क्रिकेट खेलूंगा। इंदौर में हमेशा टेनिस गेंद से क्रिकेट खेला करता था। उन्होंने कहा , यूं तो चार पांच साल से आईपीएल खेल रहा हूं लेकिन इस साल प्रदर्शन खास रहा है। टीम का भी और मेरा भी और यही कोशिश करूंगा कि लय बनी रहे। दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा और नोर्किया के साथ आवेश दिल्ली के तेज आक्रमण को काफी मजबूत बनाते हैं जो टीम की सफलता की कुंजी भी साबित हुआ है। रबाडा और नोर्किया के साथ गेंदबाजी के अनुभव पर उन्होंने कहा , मैंने दोनों से काफी कुछ सीखा है। जब भी इन दोनों में से कोई पहला ओवर करता है तो मैं उनसे पूछता हूं कि पिच कैसी है और कैसी गेंद ज्यादा प्रभावी है या क्या और कर सकते हैं। किस बल्लेबाज को कैसे गेंद डालनी है। मैदान पर काफी बात होती है और हमारा फोकस एक ईकाई के रूप में अच्छे प्रदर्शन पर रहता है। दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और भारत के मोहम्मद शमी से प्रभावित आवेश का कोई रोलमॉडल नहीं है लेकिन वे सभी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपने कैरियर में दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के योगदान का भी उल्लेख करना वह नहीं भूलते। उन्होंने कहा, रिकी सर के साथ यह चौथा साल है और मैं इतना कह सकता हूं कि वह जितने महान क्रिकेटर रहे, उतने ही उम्दा कोच भी हैं। वह मानसिक पहलू पर ज्यादा बात करते हैं। वह ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं। पिछले मैच में तीन विकेट लेने के बाद पोंटिंग से मिली तारीफ उनके लिए खास है। उन्होंने कहा , पहले वह बोलते थे कि गुमनाम नायक हूं लेकिन पिछले मैच के बाद कहा कि अब तुम गुमनाम नहीं रहे। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। तेरह वर्ष की उम्र में मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ के एक चयन ट्रायल में पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया ने आवेश को तलाशा और प्रदेश अकादमी में अंडर 16 टीम में उनका चयन हुआ। अंडर 19 विश्व कप 2016 में उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 12 विकेट लिए। रणजी कोच चंद्रकांत पंडित ने उनके खेल को निखारा और आज भी हर मैच से पहले या बाद में वह पंडित से बात करते है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट को अपना ड्रीम विकेट बताने वाले आवेश को भारत के पूर्व कप्तान से भी मार्गदर्शन मिला है जो छोटे शहर से निकलकर कामयाबी की बुलंदियों को छूने की हसरत रखने वालों के लिए मिसाल हैं। उन्होंने बताया , माही भाई ने इतने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया है।